

# हरियाणा विधान सभा

की

## कार्यवाही

28 फरवरी, 1996

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 28 फरवरी, 1996

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 1
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— गृह राज्य मंत्री द्वारा	(4) 18
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 19
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री चन्द्र मोहन द्वारा	(4) 28
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 28
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— आवास राज्य मंत्री द्वारा	(4) 30
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— गृह राज्य मंत्री द्वारा	(4) 31

104 00



(ii)

	पृष्ठ सख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)31
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(4)36
नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव	(4)37
नियम 22(2) के अधीन कार्य के कार्यक्रम में परिवर्तन करना/राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को स्थगन करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेना	(4)37
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)41
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-- चौधरी बंसी लाल द्वारा	(4)49



*ERRATA*

to

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1, No. 4, dated the 28th  
February 1996 (Second Sitting)

<u>Read</u>	<u>For</u>	<u>Page</u>	<u>Line</u>
की	कि	5	28
शब्द 'नहीं' के बाद 'था' न पढ़ा जाए		18	16
आग	आग को	20	15
रूपये	रुपय	26	24
और	आर	29	27



Table 1. Summary of the data used in the analysis.

Year	Sample Size	Response Rate	Response Rate (95% CI)
2002	4	100%	100%
2003	91	90%	85-95%
2004	92	88%	83-93%
2005	93	87%	82-92%
2006	91	86%	81-91%

Continued

## हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 फरवरी, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Sh. Karan Singh Dalal may resume his speech.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने कानून व्यवस्था की बात की है। सौरभ जैन नाम के बच्चे को आज से 20 दिन पहले उठा लिया गया था। उस बच्चे के घर वालों को 5-7 दिन बाद फोन आ जाता है कि फर्मा जगह पर 20-25 लाख रुपये पहुंचा दो, आपको अपना बच्चा सही सलामत वापिस कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज तक हरियाणा की पुलिस उस बच्चे को वापिस नहीं ला सकी है। इसी तरह से फरीदाबाद में पुलिस की कस्टडी में एक गरीब ब्राह्मण लड़का जो मजदूरों के साथ काम करता था, की मौत हो गई है। जिस सेठ ने मिलकर के उसको मरवाया है आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हेल्थ सर्विसिज के बारे में यहां पर जिक्र किया। पलवल में एक सिविल हास्पिटल है। वहां के बारे में हमने कई बार कहा है कि वहां पर हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज तक वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं लेकिन कन्ज्यूमर कोर्ट्स के बारे में हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया है। हर जिले में एक जज नियुक्त होना चाहिए ताकि वहां पर लोगों की जो शिकायतें हैं उसके लिए एक अलग से कोर्ट चल सके। इससे लोगों को काफी फायदा होगा।

इस अभिभाषण में गरीब लोगों की बात की गई है। इसमें ईसाई लोगों की चर्चा की गई है कि उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिले। अगर ये ऐसा करते हैं तो हरियाणा ही देश में पहला अग्रणी राज्य होगा जहां पर ईसाइयों को यह फायदा पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से पहले डा० अम्बेदकर के नाम से 14 अंग्रेजों की छुट्टी हुआ करती थी लेकिन इस बार यह छुट्टी इतवार की पड़ गयी

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि दलित वर्ग के लोगों की भावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार को अम्बेदकर के नाम से किसी और दिन छुट्टी अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह से सर, हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकार यह क्लेम करती है कि उसने गांव-गांव में पीने के पानी की सुविधा पहुंचायी है। लेकिन मेरे पलवल के हल्के में जितने गांव में भी सरकार ने पीने के पानी की सुविधा मुहैया करवायी है, वहाँ पर ज्यादातर गांवों में ये पानी के पाईप फटे हुए हैं जिसकी वजह से पानी रिसता है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन पाईपों के बारे में भी जितनी जल्दी हो सके सरकार को गौर करना चाहिए और उनको बदलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा में मध्याह्न पोषाहार योजना स्कूलों में लागू की गयी है। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि हमारे फरीदाबाद जिले के कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर यह योजना लागू की गयी है। हमें तो वहाँ पर ऐसा कोई स्कूल नजर नहीं आता जहाँ पर यह योजना शुरू की गयी हो।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में मंत्री जी से अलग से सवाल पूछ लेना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : ठीक है जी। इसी तरह से सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि को-ऑपरेटिव सोसायटीज के जरिए राज्य के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। वे कई महीनों से इन सोसायटीज के माध्यम से अपनी अपनी बसिज चला रहे थे। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग भी की थी कि जो टैक्स उन पर लगाया जा रहा है वे उसे देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई इतनी नहीं है। टैक्स की वजह से वे अपनी बसिज से इतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : सर, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। सर, मैंने पहले भी डिप्टी स्पीकर साहब से अर्ज किया था और अब आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, और यह कन्वेंशन भी है कि जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है उसको उसी हिसाब से टाईम दिया जाएगा। लेकिन हमें तो बिल्कुल भी टाईम नहीं मिला है। ये तो आधा-आधा घंटा बोल जाते हैं। पहले भी ये 15 या बीस मिनट बोल लिए हैं और अब भी इन्होंने पांच सात मिनट ले लिए हैं। यह इनका कोई तारीका नहीं है। हमारे मੈम्बरज को भी टाईम मिलना चाहिए। यह हैरानगी की बात है कि हमारे मੈम्बरज को टाईम नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा जिला फरीदाबाद है, वह यू०पी० के साथ लगता है। इस वजह से हरियाणा और यू०पी० के किसानों का आपस में भूमि विवाद बना रहता है। पिछले दिनों भी अखबारों में यह बात आती रही है।

कि उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा की सीमाओं में दाखिल होकर यहाँ के किसानों की फसलें काटकर ले गए और इस प्रदेश के पुलिस अधिकारी और सारा प्रशासन भाँव बन्द करके यह सारी बातें देखता रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपने किसानों की रक्षा करनी चाहिए और यू०पी० के लोग यहाँ के किसानों का नुकसान करते हैं, उसके बारे में हमें सरकारी कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा दलाल साहब कह रहे थे कि फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में एस०पी० ने बैठकर उस लड़के को भरवाया तो यह इनकी बात गलत है। वह लड़का मेरे हल्के का रहने वाला था और मेरा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको सदन में इस तरह के गलत एलीगेशन नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे सदन की गरिमा गिरती है। उस लड़के ने सुसाईड किया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उस लड़के की मृत्यु एस०पी० के कारण हुई है।

श्री० छतर पाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गवर्नर एंड्रेस पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। 26 तारीख को गवर्नर महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़कर के यहाँ सुनाया उस के पेजिज को पढ़ते वक़्त बड़ा अजीब सा महसूस होता है। जो चीजें तथ्यों से परे हों और सच्चाई से अलग हों उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। हरियाणा की विधान सभा जैसे महान सदन में तथ्यों को अस्मित करने वाली बातें कही गई हैं। मैं यह महसूस करता था कि कुछेक चीजें उसमें ऐसी मिलेंगी जिनकी तारीफ की जाती है। अगर ऐसी बात होती तो जो मुख्य मन्त्री जी को गिला है कि विपक्ष हृमेशा विरोध करता है तो मुख्य मन्त्री जी को वह गिला न हो पाता। (विघ्न) स्पीकर सर, सरकार का इसमें रैफरेंस दिया गया कि बड़ी न्यायपूर्ण सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने बड़ी ऐक्टिव और एलर्ट सरकार ने, जनहित की सरकार के कामों का जो ध्यौरा है, वह इसके अन्दर मिलता है। स्पीकर सर, पिछले सेशन में भी जिक्र आया था कि बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई। राम बिलास शर्मा जी इस बारे में विशेष रूप से प्वायंट आउट कर रहे थे कि हरियाणा में जो वर्षा हुई और बाढ़ आई, वह मैनमेड फ्लड था, प्रशासन की लापरवाही की वजह से पैदा की गई आपदा थी। मैं इसका उदाहरण बड़े स्पष्ट शब्दों में देना चाहता हूँ। सिसाए मेरी कास्टीच्यूएन्सी का एक ऐसा भाँव है, जहाँ वर्षा की वजह से हर साल फसल खराब होती है। पावर मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं बैठे हैं उनके भी कुछ ऐसे भाँव हैं जैसे पाली, राजपुर माड़ा हैं जिनमें हर बारिश के मौसम में फसल खराब होती है। जो फ्लड आया था गवर्नमेंट आर उसमें सचेत होती, संवेदनशील होती, न्यायप्रिय होती, अपनी जिम्मेदारी को समझने वाली होती तो हर व्यक्ति महसूस कर सकता था कि सरकार ठीक है। बारिश से हर साल जो भाँव प्रभावित होते हैं उन गाँवों को भी आज तक बाढ़ मुक्त करने का प्रयास नहीं किया गया। यह बड़ी जबरदस्त विडम्बना है। जिन गाँवों

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

में हर वर्ष पानी आता था उसकी बात तो समझ में आती है कि सरकार ने एक लापरवाही का काम किया वहां पर कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए जिससे उनको बचाया जा सके। जो गांव हमेशा पानी की प्यास में रहते थे जहां बाढ़ का नामो-निशान तक नहीं था वहां तक पानी बाढ़ का गया है। मैंने पिछले सत्र में भी जिक्र करने का प्रयास किया था लेकिन यहां डिसक्रिमिनेशन की बात देखने को मिलती है कि पूरी तरह से मैनबर को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। स्पीकर सर, आप हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं। आप भी कुछ सीमाओं के अन्दर बंधे हुए हैं। क्लज एण्ड प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं यह बात आज इस गवर्नर ऐड्रेस पर कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मन्त्री विशेष रूप से इस ओर ध्यान देंगे। इनको मेरे से तो शिकायत ही सकती है लेकिन उन गांवों के लोगों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। (विष्णु) स्पीकर साहब, राय पुर झाणी, सिकार पुर और न्याना, मैं भजन लाल जी की तबज्जी दिलाउंगा कि वे इन गांवों के नाम तोड़ करे। सिसाए की तरफ से व माजोद की तरफ से बहता हुआ पानी जो खरड़ अलीपुर गांव को घेर करके हिसार कन्टोनमेंट और हिसार मेजर नहर के बीच से हिसार की तरफ बह रहा था। दस दिन तक लगातार सिसाए, माजोद से जिस पानी ने क्रीस किया उसके बारे में इनका एडमिनिस्ट्रेशन अखि बन्द करके सोता रहा और वह पानी बहता रहा। इनको इतना ध्यान नहीं था कि आगे कन्टोनमेंट है जो नार्दन जॉन का डिफेंस का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। इनको यह ध्यान नहीं था कि उसको खतरा हो सकता है। यह तो मान सकते हैं कि घिराव के लोगों के डूबने की सरकार को चिंता न होती लेकिन सरकार यदि देश की सुरक्षा से संबंधित बातों का भी ध्यान न दे तो आप इसे कितनी बड़ी नैगलीजेंस कह सकते हैं कितनी लापरवाही कह सकते हैं। स्पीकर साहब, 15 दिन तक पानी जो हिसार मेजर और कैंट के बीच में बह रहा था उसका सरकार इंतजाम नहीं कर सकी। उस पानी को बाल समद ब्रांच से बेल आउट कर देते ताकि उस फलो को कम किया जा सकता। ऐसा करने से कैंट को और दूसरे गांवों को बचाया जा सकता था। अल्टीमेटली जब पानी वहां पर 15 दिन तक बहता रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्टोनमेंट के लोगों से मिल कर मेजर नहर को कटवा दिया। झाणी रायपुर, सिकारपुर और न्याना के जो एक एक या आधे आधे एकड़ के मालिक हैं वे माली का काम करते हैं, सब्जी की खेती का काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। स्पीकर साहब, उनकी जमीनों को पानी से तर कर दिया। गांव के अन्दर और खेतों के अन्दर पानी बहता रहा। जब गांव के लोग इक्ठे हो कर वहां आ गए कि ऐसी ज्यादाती हमारे साथ क्यों की जा रही है तो उनको धमकी दी गई कि अगर यहां नजदीक भी आए तो गोशियों से उड़ा दिए जाओगे। स्पीकर साहब, क्या आप इस सरकार को सबेदनशिल सरकार कहेंगे, क्या आप इस सरकार को अच्छी और अलर्ट सरकार कहेंगे। किसानों की



जो प्रोब्लम एंटीसिपेट की जा सकती थी उसको भी एंटीसिपेट न करे और उनके बचाव का कोई कार्य न करे और अपनी सर्जि से नहर को कटवा कर लोगों की तबाही की तरफ यह सरकार बढ़ी। फिर सरकार ने एक मुआवजे का एलान किया। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से 570 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में और ग्रांट के रूप में लिए। हरियाणा सरकार ने भी शायद कुछ अपने फंड से भी मैनेज किया होगा। फिर सरकार ने यह कहा कि प्रकृति की विपदा से जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। उसकी रेशो नीमिनल तय की गई जिससे खाद का कट्टा भी नहीं आता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार की लापरवाही की वजह से, कमी की वजह से और उसकी गलती की वजह से गांवों में पानी काट कर भेजा गया। उससे जिन लोगों का नुकसान हुआ क्या उनको सौ परसेंट मुआवजा देने का इस सरकार का फर्ज नहीं बनता? यदि सरकार किसी का गला घोटती है, किसी को मारती है या किसी की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ती है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री जी से अपयोरिस चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपके डी०सी० और कमिश्नर कुछ नहीं लगते, आपके तो लोग लगते हैं क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपका फर्ज बनता है कि अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर कोई लापरवाही की है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और उस जिम्मेदारी को लेते हुए लोगों को सौ परसेंट कम्पनसेट कीजिए। उसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपकी पापुलैरिटी बढ़ती है। ऐसा करने से हम भी उन लोगों को कह सकते हैं कि वाक्या ही आज जन हित की बात सरकार के माध्यम से की गई है। स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करता चाहता हूँ कि इनके अधिकारियों ने एक दिन के अन्दर बैठ कर 15-15 गांवों का सर्वे दिखाया। ट्यूबवैल्व भी चैक कर लिए, खेती के किल्ले भी चैक कर लिए कि कितने एकड़ में नुकसान हुआ है आप एक पोलिटिकल आदमी हैं और आप यदि किसी गांव का दूर करते हैं और चाँपाल में जा कर लोगों के बीच में हाथ जोड़ते हैं तो आप 8-10 गांवों से ज्यादा कवर नहीं कर सकते। इन्होंने 15-15 गांवों का रिक्कार्ड एक दिन में चैक कर दिया कि किस का कितना कितना नुकसान हुआ। क्या यह बात आपको प्रैक्टिकल लगती है? तो जो उन लोगों के साथ अभ्याय हुआ है मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूँ कि राजली, सरसौद और बिचपड़ी मेरे क्षेत्र के गांव हैं। सिसाए, माजोद, खरड़ अलीपुर और रायपुर ढाणी के लोग आज तक मारे मारे फिर रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ एफीडेविट दिए हैं। सिसाए के पटवारी के खिलाफ आठ एफीडेविट आज तक दिए गए हैं। यदि यह सरकार संवेदनशील होती तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पटवारी के खिलाफ, कानूनगी के खिलाफ और तहसीलदारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया जिन्होंने 15-15 दिन का गांवों का सर्वे एक दिन में दिखा दिया, उनके खिलाफ एफीडेविट दिए गए हैं। There is no practical survey at all उनके खिलाफ आज तक कोई

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

कार्यवाही नहीं की गई है। स्पीकर साहब, क्या मैं यह समझूँ कि सरकार के मुख्य मन्त्री और सरकार के वजीरों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पियन और पटवारी तक मिले हुए हैं। स्पीकर साहब, वे इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक व्यक्ति सरेशम रिश्तत खाता है, उसके खिलाफ एफीडेविट आते हैं। आप एफीडेविट देने वालों के खिलाफ नियम 162 के तहत कार्यवाही की जाए या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिनके खिलाफ एफीडेविट आते हैं। स्पीकर साहब, डी०सी० हिसार और एस०डी०एम० हांसी जिनके पास एफीडेविट हैं, एक व्यक्ति मुआवजे के लिए उनके पास बार-बार जाता है। मुझे पता है कि रैस्ट हाऊस हिसार में ट्रालियां भर-भर कर ली गयीं और मुख्य मन्त्री महोदय से मिले थे। मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कह दी कि मुआवजे की तारीख चली गयी है, अब आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि मुख्य मन्त्री जी इस बात के बारे में कहेंगे कि स्पीकर साहब, मैं आन दी फ्लोर आफ दी हाऊस यह बात कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जल्दी में मेरे मुँह से यह बात निकली होगी। यदि यह बात है तो आज तक मुआवजा क्यों नहीं मिला मुझे समझाइये। उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। मुख्य मन्त्री जी आश्वासन दे देते तो उन लोगों के दिल में मुख्य मन्त्री के लिए बड़ी जगह बनती। मैं मन्त्री जी की तारीफ कलंगा जो बातें मैंने बताया है, जो मेरी कास्टीच्यूएंसो से संबंधित है अगर आप उनके प्रति एक्शन लें। (व्यवधान)

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : प्रो० साहब आप एफीडेविट की बात कर रहे हैं। आप एफीडेविट की बात तो छोड़िए आप एक सिम्पल एप्लीकेशन ही दिला दें फिर देखें कि एक्शन होता है या नहीं होता है।

Prof. Chhattar Pal Singh : If you have any doubt, why don't you enquire this thing from your Deputy Commissioner or S.D.M., whether such affidavits have been given or not. If you do it, I shall be grateful to both of you. (Noise & Interruptions). मैंने लिखकर भेजा है और आपके डी०सी० साहब से भी बार-बार मिला हूँ। मुख्य मन्त्री जी आप पर मैंने शक कर लिया था इसलिए मैं नहीं आया हूँगा लेकिन आपके पास लोग गये थे। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैंने आपको मुकानों के मुआवजे के मुतलक रैफरेंस दिया है। जो पशुओं के मुआवजे के मुतलक है, जो उन लोगों के एग्जीक्यूटिव लीसिज के मुतलक है उस बारे में स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार एक बात तय कर दे कि एनीमल का जो लीस हुआ है उसका भी मुआवजा मिलेगा? दूसरी तरफ जो भेड़ों का काम करते थे उनको घोषणा कर दी गई सिसाए में। भेड़ बकरियों के अनेकों ऐसे केन्द्र हैं जिन्हें कि लोग चलाते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। स्पीकर साहब, सरकारी सम्पदाओं की मैटीनेंस के लिए पैसा दिया गया है। स्पीकर साहब,

में अनेकों रोडज के नाम आपको काउंट करवा सकता हूँ जिन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ और जबरदस्त गड़बड़े बने हुए हैं। जैसे सबलपुर भादों से राजली होते हुए, बरवाला से हांसी होते हुए, बणासों से लेकर घिराय होते हुए हिसार-हांसी को जो रोड मिलता है उसकी भी हालत खराब है। स्पीकर साहब, दौलतपुर पेठवाड़ तक जाया फरीदपुर जो रोड जाता है उसका भी बुरा हाल है। खेड़ी से उकखाना जो रोड जाता है उसकी भी हालत खराब है। शाहू से कनाला जो रोड जाता है उसका भी यही हाल है। रायपुर ड़ाणी और सिकारपुर जहाँ पानी आज तक भी खड़ा है, वह सारा रास्ता बहुत खराब है। महाद और सिसाए रोड पर पांच-छः साल से पत्थर और रोड़े पड़े हैं, वह पैसा वेस्ट होने लग रहा है। आज तक उस सड़क का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ है। सिसाए से हांसी और जीन्दकी जो सड़क है, उसका बुरा हाल है। स्कूलज, हास्पिटलज तथा और भी गवर्नमेंट की प्रोपर्टीज है, यह गवर्नमेंट का अपना धन है, उसकी सेन्टीनेंस पर जो पैसा सरकार ने दिया है मैं उसको समझने में असमर्थ हूँ। यह जनहित की सरकार है। यह सरकार इस तरफ तबज्जो क्यों नहीं दे रही है? स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गुजारण करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार यह एशयोरेंस दे कि फलड से जो नुकसान हुआ है उसका दोबारा से सर्वे कराया जाएगा। उसके आधार पर जिन अधिकारियों ने कोताही की है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए और लोगों को कम्पनसेट किया जाए। यहाँ पर जिक्र आया कि यह सरकार जनहित की सरकार है।

श्री अध्यक्ष : आप वाइंड-अप करें।

Prof. Chhattar Pal Singh : Sir, I will try to wind up my speech within 5 or 10 minutes. Sir, I am relevant today. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष : वैसे तो आप ठीक बोल रहे हैं।

श्री० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ और मैं ठीक ही बोलूंगा, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय देंगे। मैं अच्छा ही बोलूंगा। एक बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न के अन्दर वोटर्स को पूरी तरह से शिक्षित नहीं किया जाएगा तो पोलिटिशियंस उनकी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। जो व्यवस्था सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा की पोलिटिक्स के शीम पर आई, उसका एक ही कारण है कि मतदाता अपनी छोटी-छोटी मजबूरियों की वजह से, बिना किसी मैरिट-डिमरिट को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालने के लिए मजबूर था और पोलिटिशियंस मजबूर थे कि वे उनकी इच्छाओं के मुताबिक काम करें।

Today the situation is changed. The situation is that the leaders are led by the people and not that the people are led by the leaders. जिन लोगों ने वोट देने हैं, लीडर उनको फाली करने का प्रयास करते हैं चाहे वे ठीक कहें चाहे गलत कहें क्योंकि उन्हें दोबारा विधान सभा या पार्लियामेंट में बैठने की



[श्री० छत्तर पाल सिंह]

लासला होती है। इससे व्यवस्था बिगड़ती जाती है। यदि सरकार एजुकेशन पर तबज्जो देती तो अच्छा होता। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने स्कूलों का रेड किया और कितने स्कूलों की व्यवस्था को चेक किया कि आया टीचर्स सुबह से शाम तक स्कूलों में बैठते हैं या नहीं और सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। स्पीकर साहब, दिल्ली के अन्दर पिछले 46 दिन से अध्यापक घरने पर बैठे हुए हैं। उसके बारे में विधान सभा के अन्दर भी एक क्वेश्चन आया था। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा होता यदि दो दिन, पांच दिन या 10 दिन के बाद मुख्य मन्त्री जी उनको बुला कर मामला सैटराइट करते और कहते कि बच्चों की पढ़ाई वेस्ट हो रही है, आपकी जो जायज मांगें हैं उनको सरकार मानेगी तो विधान सभा में वह सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी को आभास होगा और याद भी होगा जब मैं इनकी कैबिनेट में टेक्नीकल एजुकेशन मिनिस्टर था। उस समय मैंने इनकी सुविधा के लिए लड़ाई लड़ी थी। टेक्नीकल एजुकेशन के रिजल्ट्स भी आए। मुख्य मन्त्री जी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत थे कि दिन रात रेड करके दिन रात भागदौड़ करके टेक्नीकल एजुकेशन का नाम हरियाणा में इस टैग्योर के अन्दर उभर कर आया है। वह सिर्फ इसलिए था कि यदि आप टीचर्स के इंटैस्ट को देखेंगे तो आप उनसे 24 घंटे काम लेना भी मुनासिब समझेंगे और टीचर्स काम करना भी पसंद करेंगे। टीचर्स की बदलियों से हमें कुछ नहीं लेना देना, उनको आपने जहाँ पर उठा कर फैंकना है फैंक दें। जहाँ पर बदली करनी है वह कर दें, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। यदि कोई टीचर अपने गांव में रह कर बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो बच्चों को गांव में भी पढ़ाया जा सकता है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स क्षेत्र के अन्दर विलेज डिवैल्पमेंट की बात को ले कर जो चीज लिखी गई है, मैं समझता हूँ कि आज शारीरिक व्यवस्था की आवश्यकता है और सरकार उसको पूर्ण रूप से इन्तोर करने की कोशिश कर रही है। स्पोर्ट्स क्षेत्र में जो जो लड़के मैरिट पर हैं उनको प्रायटी के आधार पर रिजर्जेशन दे कर सविस दी जाए और उनकी कोई पर-सैटेज तब की जाए। इससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी और मजबूत रहेगी। चीफ मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे कि विलेज डिवैल्पमेंट के लिए जो पैसा जाता रहा है उसके बारे में डिवैल्पमेंट मिनिस्टर ने आज तक कोई चेकिंग नहीं की। जिस किसी वी०डी०ओ०, एक्सीयन या जे०ई० ने इस बारे में कोई गलती की है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। गांवों की गलियों में इंटेंडल्टी सीधी लगा देते हैं और उन इंटेंडों को दूसरे या तीसरे साल पाइ कर लैवल को बदलना पड़ता है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ और यह बात मैंने पिछले सेशन में भी कही थी कि एम०एल०एज० को उनकी कांस्टीच्यूएसी में डिवैल्पमेंट के काम करवाने के लिए जो 20 लाख रुपए की किश्त जाती है वह पूरी नहीं जाती है। वर्ष 1994-95 में मुझे 20 लाख रुपए में से केवल 8 या साढ़े 8 लाख रुपए ही

ही मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि यह पैसा मुझे किस डिस्ट्रिक्मिनेशन के तहत दिया गया। मैं समझता हूँ कि सरकार मुझे वह पैसा पूरा करके देगी। आज भी आपने एनुअली 50 लाख रुपए देने के बारे में अनाउंस किया है, वह भी मेरे हल्के को पूरा नहीं मिला है। मैं चाहूँगा कि जो पैसा विधायक की डिस्पोजल पर दिया जाए वह पूरा दिया जाए। वह पैसा विधान सभा के स्पीकर का नहीं है, यह पैसा चौधरी भजन लाल जी का नहीं है। वह सरकार का पैसा है। बार-बार 15.00 बजे लोग उसके अन्दर कमीशन खा रहे हैं। उन गलतियों का सैबल ठीक नहीं है। We are wasting the money. We are not serving the villagers. तो स्पीकर साहब, मैं डिवलपमेंट मिनिस्टर से यह चाहूँगा कि वे गांवों की डिवलपमेंट की तरफ विशेष ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : पंचायत का भी फर्ज बनता है कि वह देखे कि आया काम ठीक हो रहा है या नहीं। वे सारे काम को सुपरवाइज कर सकती हैं।

श्री० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायतें यदि ठीक ध्यान नहीं दे रही तो जो बी० डी० ओज० के माध्यम से काम हो रहा है उस पर सरकार को नजर रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपका समय हो गया।

श्री० छत्तर पाल सिंह : मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूँ। आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री० छत्तर पाल सिंह : I am very grateful to you for extending my time. यहाँ पर एस०वाई०एल० का जिक्र आया है। इस मुद्दे पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है और हरियाणा में भी है। मैं इस बात को समझता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर की एक पोलिटिकल समस्या हो सकती है at the cost of the State interest and at the cost of the farmers interest. स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि भजन लाल जी इस बात में बड़ी भजवृत्ति दिखायें जिसमें कोई अपोजीशन का सदस्य, आपका वजीर और आपका एम०एल०ए० भी इंकार नहीं करेगा। आप स्टेट के इन्ट्रिस्ट के लिए एक प्रस्ताव पास करके भेज दें कि एस०वाई०एल० नहर जल्दी बनायी जाये। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो सारी जनता आपके साथ होगी और प्रदेश के लोग समझेंगे कि भजन लाल जी वाकई इस मुद्दे के प्रति सज्ज हैं। भले ही प्राईम मिनिस्टर इस बात को न मानते लेकिन लोगों तक आपकी बात तो पहुंच जाती कि आप इस मुद्दे के प्रति चिंतित हैं और वाकई इस नहर के बनाये जाने में आप का इन्ट्रिस्ट है।

[श्री० छत्तर पाल सिंह]

एक बार अखबार में छपा कि श्री० छत्तर पाल सिंह इस नहर के मुद्दे पर तारतम्य से यात्रा करेंगे और दिल्ली में प्रधान मंत्री जी से इस बारे में भेंट करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा भारी ताज्जुब हुआ जब भजन लाल जी ने इस बारे में एतराज किया। इन्होंने मुझे कहा कि आप एस०बी०आई०एल० नहर के बारे में कोई यात्रा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि यह तो स्टेट के इन्स्ट्रुमेंट की बात है और आपके फेवर की बात में करूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गयी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एण्ड आर्डर की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर कहा गया था कि राम राज कायम होगा। यदि राम राज कायम नहीं हुआ तो कम से कम लोगों की सुरक्षा का तो इंतजाम होना चाहिए। स्पीकर साहब, इस बात से सभी सहमत होंगे कि इस सरकार के आने के बाद अनेकों कांड हुए। कादमा कांड हुआ। वहाँ पर अनेकों किसान मारे गए। गोली चली। फिर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है। यदि सही ला एण्ड आर्डर होता तो कादमा कांड न होता। राम बिलास जी ने भी अखबार का यह चित्र दिखाया था। स्पीकर साहब, यदि इस चित्र को आप देख लेंगे तो आपका कलेजा भी हिल जाएगा। रेणुका के साथ आठ-आठ आदमियों ने रेप किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। केस सी०बी०आई० को चला गया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या हम यह समझें कि इसमें कोई मंत्री या विधायक की संलिप्तता है। इसी प्रकार से करनाल में द्रौपदी कांड हुआ। उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज जनता का हरियाणा की पुलिस से विश्वास उठ गया है। पहले हरियाणा की पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती थी लेकिन अब पता नहीं क्यों यहाँ की पुलिस किसी केस में एक्शन नहीं लेती। क्या इसमें हम यह समझें कि इन कांडों में सरकार का कोई चहेता शामिल है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी से गुंजारिश है कि इस किस्म की बदमजगी यहाँ पर न फैलने दें। जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई भी केस हो जाये तो लोग सी० बी० आई० की जांच की मांग करते हैं। यहाँ की पुलिस से लोगों का विश्वास उठ गया है। तीन तीन आई० पी० एस० अधिकारियों को कोर्ट से सजा होती है लेकिन फिर सरकार उनको रि-इन्स्टेट कर देती है। रिक्लूटमेंट में गड़बड़ होती है और कोर्ट से 1700 सिपाहियों को मौकरी से हटाने के आदेश होते हैं। स्पीकर सर, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लोगों से जो रिक्लूटमेंट के लिए 40-40 हजार रुपए लिए गए थे, मैं मानता हूँ कि ये अकड़ें आपके संत्राल के नहीं हैं लेकिन जिन अधिकारियों, जिन लोगों ने लिए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। यदि लार्ज स्केल पर रिक्लूटमेंट रद्द होती है तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है। मुख्य मंत्री महोदय यह स्थिति स्पष्ट करें। मुख्य-मंत्री महोदय, आप लोगों को बताएं कि जिन लोगों ने यह पैसा लिया है। उनके



खिलाफ क्या कार्यवाई हुई है ? अध्यक्ष महोदय, कोई एस० पी० या डी० आई० जी० जिन्होंने इनको इंडीकेट किया कि गलत रिक्लूटमेंट होने लग रही है क्या उनको कोई रिवाई आपने दिया। जिन अधिकारियों की रैंजिंग में यह गलत रिक्लूटमेंट हुई बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी रूज रैगुलेशन के उसके बावजूद भी इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की। On moral grounds, the Home Minister should resign. यहाँ केवल 40-40 हजार की बात नहीं है, यहाँ तो करोड़ों के हवाले की बात है। करोड़ों रुपए खर्च जाते हैं। मैं यह अश्वोरिस चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय, आप इन सारी बातों का हाऊस में जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री धीरू गोम प्रकाश बेरी (बेरी): अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया, उस पर सदन में चर्चा हो रही है। पहले तो मैं एक नैतिकता का सवाल रखता हूँ। इस सरकार के सिर्फ दो या अर्धवर्ष महीने रहते हैं और जो अभिभाषण राज्यपाल ने सदन में सरकार की तरफ से पढ़ा, वह आने वाले 1996-97 साल के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट है। नीति संबंधी ब्यान तो अगली सरकार को देना होता है। इस सरकार को नीति संबंधी ब्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। औपचारिकतावश यह अच्छी बात होती अगर वे सेशन के समय नीति संबंधी ब्यान न देते लेकिन इन्होंने अपनी जिद करके अभिभाषण में अपना नीति संबंधी ब्यान दिलवा लिया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हाऊस में यह आधार बन गया है। इसके बारे में दो तीन प्वायंट्स धन्यवाद प्रस्ताव में आए हैं, मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले पैरा नं० 3 में राज्यपाल महोदय ने हरियाणा प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था का जिक्र किया है और क्लेम किया है कि साल 1995 में प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। लेकिन इस बात की जनता गवाह है कि आज प्रदेश के अन्दर कानून का राज नहीं है, जंगल का राज कायम है। बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट इस प्रदेश के अन्दर आज एक उद्योग की तरह से विकसित हुए हैं। इसका उदाहरण एक नहीं सैकड़ों मिल सकते हैं। 1995 के, 1994 के, 1993 के तथा 1992 के मिसाल हैं। 1991 से इस सरकार का राज है। करीब पौने 5 साल इस सरकार को बने हुए ही गए हैं। अगर मैं इसको कांडों की सरकार कहूँ तो बिल्कुल उचित बात होगी। इस बात के गवाह कौन कौन से कांड हैं। द्रौपदी कांड करनाल का, रेणुका कांड अमृता-नगर का।

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें पहले कई बफा आ चुकी हैं इसलिए इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्रीधरी श्रोम प्रकाश बेरी : मैं इसकी डिटेल् में नहीं जा रहा हूँ। किसानों पर गोलियाँ चलाई गईं। नारनौल कांड, पिरथला कांड, टोहाना कांड, कादमा कांड, भूतभाजरा कांड और हमारे इलाके के बहादुरगढ़ में, 6-6, 7-7 साल की छोटी-छोटी बच्चियों का अपहरण करके, उनका बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर दी गईं। यह इस बात का समूह है कि प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर रह गई है। अध्यक्ष सहोदय, मुख्य मन्त्री जी के दामाद से सम्बन्धित मुकद्दमें में एक आई० पी० एस० अधिकारी और पुलिस के 2 कनिष्ठ अधिकारियों को जेल भेज कर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था की पील खोल करके रख दी है। जब वे अधिकारी जेल काट कर आए तो बजाय उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करवाने के अति ही उनको डिप्यूटी पर बिठा दिया। इससे साफ जर्हिर होता है कि सरकार उन पर दबाव डाल कर उनसे गलत काम करवा रही थी, गैर कानूनी काम करवा रही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले कर उनको सजा देने का काम किया। दूसरे कई केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आई० पी० एस० अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के कई अन्य कनिष्ठ आफिसरों को जेल भेज कर सरकार को कटघरे में ला कर खड़ा कर दिया है। हरियाणा पुलिस पर आज लोगों को एतबार नहीं रहा। इसी कारण जब भी कोई घटना हो जाती है तो जो इन्फोरमेंट होता है वह बार-बार कहता है कि मेरे मुकद्दमे की जांच सी० बी० आई० से होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि आज 14 केसिज में सी० बी० आई० जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस कतई निष्क्रिय हो चुकी है और लोगों का इस पर से कतई विश्वास उठ चुका है। बार-बार मामलों में सी० बी० आई० से जांच होने की बात हो रही है। इसका एक उदाहरण छतरपाल सिंह जी ने दिया था। मैं भी उसको थोड़ा सा दोहराते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। सिविल साइत, हिसार थाने में एफ० आई० नं० 0-29 डेटिड 9-1-1993 दर्ज हुई और मुख्य मन्त्री ने आशवासन दिया कि पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ जिन्होंने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है, जरूर जांच की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस विधान सभा में भी यह बात उछाई गई थी और विधान सभा में भी मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वे इस मामले में इन्साफ करेंगे। आज तीन साल बीत गए हैं, तीन साल इन्तजार करने के बाद आज हाई कोर्ट में मुकद्दमा डालना पड़ा है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्य मन्त्री जी इस बात का जवाब दें कि क्या कारण था जिसकी वजह से 3-3 साल से एफ० आई० नं० 0 दर्ज होने के बाद भी मामले में कार्यवाही नहीं हुई, मामला विचाराधीन पड़ा रहा। क्या यह मामला पोलिटिकल आधार पर दर्ज किया गया था और बाद में कोई पोलिटिकल प्रेशर पड़ गया जिसकी वजह से उस पर कार्यवाही नहीं हुई। इस बारे में मुख्य मन्त्री जी और सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए ताकि हरियाणा की जनता को पता लग सके कि यह सरकार किस ढंग से काम कर रही है। जब-जब किसान या दूसरे लोग अपनी भांगों

को लेकर आन्दोलन करते हैं, एजिटेशन करते हैं तो सरकार उनकी मांगे मानने की बजाये उन पर गोलियाँ चलाने का काम करती है। आज पूरा अध्यापक वर्ग इस बात को ले कर खूब है कि हरियाणा सरकार के बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी उनकी मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया, उनकी मांगों को मानने की बात तो छोड़ दीजिए। मजबूर हो कर और दमन चक्र से डर कर हरियाणा प्रदेश के अध्यापक दिल्ली में अपना आन्दोलन चला रहे हैं। उनके पदाधिकारी मास्टर राम पाल बहिया का आज 47वां दिन अभिरण अनशन पर बैठे हुए हो गया है और दूसरे पदाधिकारी श्री तहलान का 33वां दिन अनशन पर बैठे हुए हो गया है।

**श्री अध्यक्ष :** बेरी साहब, ये सब बातें तो पहले आ चुकी हैं, आपने कोई और बात कहनी ही तो कहिए।

**श्रीधरी श्रीम प्रकाश बेरी :** स्पीकर सर, अगर मुझे बोलने का हक न हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। उनकी बात मानने की बात तो छोड़ दीजिए सरकार ने उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। यह इस बात का नमूना है कि सरकार कर्मचारियों के साथ किस प्रकार की सहानुभूति रखती है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे हाउस में आश्वासन दें कि जो उनकी बट्टीपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने बारे मुख्य मांग एक अर्से से चली आ रही है उस पर विचार करेंगे। इससे कोई लम्बा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, अध्यापकों की इससे मदद हो जाएगी। सरकार बट्टीपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को मान कर अध्यापकों से कहे कि वे अपना अनशन छोड़ दें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, पैरा नं० 13 में राज्यपाल महोदय ने बाढ़ के बारे में जिक्र किया है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार ने अप्रैल, 1995 से जुलाई, 1995 तक बाढ़ रोकने की तैयारी के नाम पर करोड़ों रुपये के कूटे बिल बना कर अपनी जेबों में डालने का काम किया है जबकि न तो किसी ड्रेन की खुदाई हुई और न किसी नहर की खुदाई या सफाई की गई। 3-4 सितम्बर को जब बारिश हुई उससे जान माल की तबाही हुई और नहरों में पूरा पानी छोड़ने से इसको और बीभत्स बना दिया। लोगों की हालत बद से बदतर होती चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक प्रकोप की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत जबरदस्त बारिश हुई और बारिश की वजह से हरियाणा प्रदेश के अन्दर भारी तबाही हुई। सरकार का फर्ज बनना था कि लोगों को इस तबाही से राहत प्रदान करने का काम करती लेकिन 15 दिन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं दी। डीजल पम्प और इलेक्ट्रिक मोटर्स खराब हुई पड़ी थीं लेकिन सरकार ने उनको ठीक कर-बाता उचित नहीं समझा और न ही ड्रेनों की सफाई करवाना अपना काम समझा। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो बाढ़ आई यह इस अध्यापकी सरकार के लिए एक



[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

वरदान साबित हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्र सरकार से 700 करोड़ रुपया आया है, इसको देने में इतनी धांधली हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है उनके बारे में इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इन-इन लोगों को मुआवजा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर रबी की फसल नहीं हुई है वहां पर भी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारे इलाके में ईख की फसल बर्बाद हो गई है लेकिन वहां पर लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। यहां से रैवेन्यू डिपार्टमेंट ने आर्डर कर दिए कि ईख की फसल वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी ईख की फसल बर्बाद हुई है उनको भी मुआवजा दिया जाए। इस बारे में सदन में मुख्य मन्त्री जी आश्वासन दें। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जिनकी गेहूं की फसल खेतों में बर्बाद हो गई थी उन लोगों को भी मुआवजे से वंचित करने का काम किया गया है। मैं सरकार से कहता हूं कि इस मामले पर भी विचार करे। इसी प्रकार से बाढ़ के दौरान जिन लोगों के मकान गिर गए थे जिनके मकानों में दरारें आ गई हैं उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। उन लोगों को भी मुआवजे से वंचित कर दिया गया है। सरकार को वहां पर दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए और जो लोग रह गए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही तीसरी बाल बिजली के बारे में पैरा नं० 17 है। इस बारे में तरह-तरह की योजनाओं का जिक्र किया गया है कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करने जा रहे हैं। आज हरियाणा में तीन-तीन गुणा बिजली का बिल देने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। \* \* \*

\* \* \* \* \*

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये जो 50 लाख रुपया बिजली बोर्ड को देने की बात कह रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये किस विषय पर बोल रहे हैं। इस बात को कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, पैरा नं० 16 में एस० वाई० एल० नहर बनाने के बारे में कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जून 1991 में जब यह सरकार आई तो उस वक्त मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि एस० वाई० एल० नहर कम्पलीट करवाने के काम के आगे भजन लाल का नाम लिखा होगा। लेकिन आज तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगवाई गई है। इसी तरह से यमुना

\*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वाटर एकोर्ड 12 फरवरी 1952 में हुआ था। जिसमें पानी का सिर्फ दो ही सूबों का हक था। ये सूबे थे हरियाणा और यू० पी०। लेकिन इन्होंने हरियाणा का हक दिल्ली को दे दिया, राजस्थान को दे दिया, हिमाचल को दे दिया और यू० पी० को दे दिया। सरकार यह भी कहती है कि हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मैं आपको दो महीने पहले की बातें बता रहा हूँ, अब का तो मुझे पता नहीं कि काम शुरू हुआ है या नहीं। लेकिन दो महीने पहले तक तो वहाँ पर एक ईंट लगने का काम भी शुरू नहीं हुआ था। हालाँकि इन्होंने वहाँ पर विद्याचरण शुक्ल को लाकर उसका फाउण्डेशन स्टोन रखवा दिया था लेकिन वहाँ दो महीने पहले तक तो काम शुरू नहीं हुआ था। अगर अब हो गया हो तो अच्छी बात है। सर, इनको बूँटा क्लेम नहीं करना चाहिए।

श्री जगदीश नेहरा : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने आपसे भी और फिर स्पीकर साहब से भी गुजारिश की थी कि हमारे पास जो मैम्बरज हैं उनको उनकी संख्या के हिसाब से टाईम मिलना चाहिए। हम आपको कल से कह रहे हैं और हमने आपको अपने मैम्बरज के दस नाम दिए भी हुए हैं किन्तु हमारी तरफ से अभी तक एक मैम्बर भी नहीं बोला। ये लोग आधा-आधा घंटा बोल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें भी टाईम अलौट किया जाना चाहिए। अगर अनअटेंड्ड मैम्बर भी आधा-आधा घंटा बोलेंगे तो फिर कैसे हमारे मैम्बरज को टाईम मिलेगा ?

श्रीधरी बंसी लाल : आप तीन दिन और हाउस का टाईम बढ़ा दो लेकिन आप हमारे मैम्बरज को बोलने दें। मुख्य मंत्री जी से भी इस बारे में बात हो चुकी है।

श्रीधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सारे मैम्बरज बोलने जरूरी हैं ? आम तौर पर तो पार्टी के लीडर ही बोलते हैं लेकिन फिर भी हमने कहा कि सब लोग बोल लें और सब लोग बोलेंगे भी।

श्रीधरी बंसी लाल : लेकिन हमारे मैम्बरज को तो अपनी बात कहने का मौका मिलना ही चाहिए।

श्रीधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप पिछला विधान सभा का इतिहास उठाकर देख लें। क्या सभी पार्टीज के सभी लोग बोलते हैं ? कल भी काफी लोग बोल लिए हैं और आज भी राम विलास शर्मा, कर्ण सिंह बलाल बोल लिए हैं। इनके तो केवल सात ही मैम्बर हैं और सात में से भी ये आधे बोल लिए हैं। बंसी लाल जी भी कल काफी देर तक बोल लिए हैं। अब क्या आप सारे बोलेंगे ? अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारी तरफ से भी पहले तीस लोग बोलेंगे।

श्रीधरी बंसी लाल : लेकिन कल तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सभी लोग बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल : मैंने यह कहा था कि सभी पार्टीज के लोग बोलेंगे । मैंने यह नहीं कहा कि सभी मैम्बर्ज बोलेंगे ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर है । सर, बेरी जी तो बहुत ही रैलेवेंट बोल रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल : यह रैलेवेंट का सवाल नहीं है । क्या हमारे मैम्बर्ज गलत बोलेंगे ?

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कहना था वह 60 आदमियों की तरफ से कह दिया । इन्होंने तो जो लिखा हुआ डाकुमेंट है वही पढ़ना है । विसला जी ने इतने गजब से उसको मूव कर दिया और लहरी सिंह जी ने उसको सैकिण्ड कर दिया तो फिर यही बात खत्म हो गयी । सर, यह 60 मैम्बर्ज का सवाल नहीं है यह तो क्लिग और अपीजीशन का सवाल है । जो यहाँ पर आज 16 माननीय विधायक नहीं हैं तो वह हिस्सा भी तो अपीजीशन वालों को मिलना ही चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये उनका इस्तीफा दिलवाकर राजी हो रहे हैं और आजकल इनकी उनके साथ सगाई होने की बात भी चल रही है, रिश्ता होने की बात चल रही है । इधर बंसीलाल जी की तरफ से भी ये सगाई करने की सोच रहे हैं । पता नहीं ये कितनों से रिश्ते करने वाले हैं और इसलिए ही आजकल इनका दिमाग खराब हो रहा है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी की ही सरकार रिश्ते जुड़वाने में लगी हुई है । पुलिस में भर्ती हुई तो इन्होंने उन लड़कों के पहले से हुए रिश्ते तुड़वा दिए, एक्सार्डिज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की भर्ती रद्द हुई तो इन्होंने उनके भी रिश्ते तुड़वा दिए और पटवारियों की भर्ती रद्द हुई तो इन्होंने उन लड़कों के रिश्ते भी तुड़वा दिए । जब आजकल मुश्किल से हमारी बात बन सकी है तो ये उस रिश्ते को भी तुड़वाना चाहते हैं लेकिन हम यह रिश्ता तोड़ेंगे नहीं । हम हरियाणा के हित में जरूर जुड़ेंगे और सारे विपक्ष को इकट्ठा करेंगे ।

चौधरी भजन लाल : हम तो चाहते हैं कि यह रिश्ता होना ही चाहिए क्योंकि बी० जे० पी० में बहुत से भाई क्वारें जो हैं ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : हम सारे विपक्ष को जरूर इकट्ठा करेंगे ।

श्री जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इनका पहले भी दो बार उनसे रिश्ता हुआ था जो कि टूट गया । इन्होंने बी० जे० पी० वालों को पीट-पीट कर निकाला था । इनको पहले उन्होंने 1977 में और फिर 1987 में निकाला है । फिर अब



ये उनसे तीसरी बार रिश्ता क्यों कर रहे हैं, क्या इनको लज्जा नहीं आती है ?  
(धीर)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि पालियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर को रूज का भी पता नहीं है कि प्वायंट आफ आर्डर होता क्या है। मैंने कोई बात की होती और उसमें से कोई बात एराइज होती तो यह बात हो सकती थी। मुझे दुख है कि इनको रूज का ही पता नहीं है। मैं सिंचाई के बारे में जिक्र कर रहा था कि दो महीने पहले हम हथनी कुण्ड बैराज देखकर आए हैं। वहां कोई काम नहीं हुआ है, एक ईंट भी नहीं लगी है, कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा है। यह तो हरियाणा की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चौधरी भजन लाल जी की एस० वाई० एल० बनाने की अगर इच्छा शक्ति होती तो आराम से 6-7 महीने में यह काम हो सकता था। भारत सरकार कर्नाटक सरकार पर दबाव डालकर तमिलनाडू को पानी भेज सकती है तो पंजाब पर दबाव डाल कर हरियाणा में एस० वाई० एल० क्यों नहीं बनवाई जा सकती। इनकी इच्छा शक्ति उस वक्त सदन में पूरी तरह से साफ हो गई थी जब इन्होंने कहा था कि यह बड़ा पेचीदा मामला है, इस पर ज्यादा लम्बी बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, सारा टाइम तो इन्होंने मेरा ले लिया है मुझे 5-7 मिनट का टाइम और दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला हो चुका है और यह बात कानूनी तौर से सही है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। यह तो पोलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इनका जनता को नहरी पानी पहुंचाने से कोई सरोकार नहीं है। दक्षिणी हरियाणा के सात जिलों के पानी के बंटवारे में भेदभाव किया जा रहा है। तीन साल पहले मैंने इस सदन में रिपोर्ट भी पेश की थी। रिपोर्ट पेश करने के बाद भी सरकार ने हमारे जिलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं समझी। तो हम इनसे इस किसम के इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुझे खुशी होती यदि गवर्नर साहब अपने एड्रेस में जे० एल० एन० की सीपेज को परमानेंट तौर पर खत्म करने की बात कहते। सीपेज की वजह से हरियाणा का हजारों एकड़ रकबा बर्बाद हो चुका है। पहले जब मैं 1982 से लेकर 1987 तक मंत्री था तो मैंने बार बार सरकार का ध्यान दिलाया कि सीपेज की वजह से किसान बहुत परेशान हैं। इस सीपेज को चैक किया जाए लेकिन आज तक उसका जिक्र तक नहीं किया गया। उस वजह से 30-40 हजार एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है। इसी प्रकार से पैरा 11 में राज्यपाल महोदय ने गांवों में शराब पर अंकुश लगाने की बात कही

[चौधरी श्रीम प्रकाश बेरी]

है। प्रकाश लगाने से बात बनने वाली नहीं है क्योंकि 10-15 किलोमीटर के फासले पर छोटे छोटे कस्बे हैं। वहाँ शहरों से लोग शराब ला सकते हैं इसके अलावा जिस गाँव में ठेका नहीं है, वहाँ ठेकेदारों ने अपने सब कंट्रेक्टर बनाकर शराब बेचने का काम किया हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरे माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल ने चर्चा की थी कि हमारे गृह मंत्री के गनमैन की हत्या हुई है। गृह मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में फरमाया था कि उसने आत्महत्या की है। यह बहुत सीरियस मैटर है। क्या गृह मंत्री जी को किसी पत्र के द्वारा ऐसी जानकारी मिली है या कोई और जांच हुई है जिससे पता चला हो कि उसकी हत्या कैसे हुई? इस बारे में वे कृपया इस सदन को बता दें।

### वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

#### गृह राज्य मंत्री द्वारा

गृह राज्य मंत्री (श्री सुभाष बतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्स-प्लेनेशन है। पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि वह मेरा गनमैन नहीं था था बल्कि वह सिक्योरिटी के गार्डज में से एक था। दूसरी बात यह है कि उसने सु-साइड किया है। उसका बाकायदा पोस्ट मार्टेम हुआ है जिसकी रिपोर्ट आई है। वहाँ के एस० पी० ने बाकायदा प्रेस को स्टेटमेंट दी है। आप इसकी जांच करवा लें, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इसलिये ये जो मेरे ऊपर एलोगेशन लगा रहे हैं यह झूठा और बे-बुनियाद है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि वह मेरे यहाँ नहीं रहा बल्कि वह तो छुट्टी पर था और उसकी मौत उसके मकान पर ही हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह गनमैन नहीं था बल्कि गश्त वाला एक सिपाही था। हम तो उसको भी सिपाही ही मानेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस ने आत्म हत्या की तो क्या उस ने जहर खाया था अपने आपको फांसी लगाई?

श्री सुभाष बतरा : यह मौत उसके घर पर हुई है और वह बाकायदा पाँच दिनों से छुट्टी पर था। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोग पता नहीं रोज कितने सु-साइड करते हैं। इसलिए आप उनके घर पर जा कर पूछें। उस की बीबी है, उसका लड़का है, परिवार के और सदस्य हैं। यह कौन सी बात करते हैं?

आप इनका पिछला रिकार्ड देखें । इनको तो सारी बातें अपने जैसी ही नजर आती हैं ।

**मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :** उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस में बिकस करने का मीटर नहीं है । या तो उसके घर वाला कोई शिकायत करता या कोई मुकदमा दर्ज करवाए या कोई किसी के बारे में शक की बात बताए तब तो उस पर सरकार कार्यवाही करेगी । अगर सरकार फिर भी उस पर कार्यवाही न करे तो इनका ध्यान उस प्वायंट को रोज करने का अधिकार है । क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं है वैसे ही कहीं से टांग पकड़ कर किसी मामले को उठा लें यह ठीक नहीं है । पहले ये तह में जाए कि क्या बात है ।

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री मनी राम (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिसला जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज की सरकार 1991 में बनी थी । इस सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से हरियाणा की तरक्की के लिए एक नारा दिया और वह नारा शान्ति और विकास का था । सरकार ने शान्ति के साथ प्रदेश में विकास करने का भी संकल्प लिया और चारों तरफ चहुँमुखी प्रगति की । चाहे नौजवानों की बात हो या महिलाओं की बात हो या बच्चों की बात हो और चाहे बुजुर्गों की बात हो, चहुँमुखी प्रगति इस प्रदेश में हुई । उससे पहले इस प्रदेश ने बहुत शपेड़े खाए । सब से पहली बात तो यह है कि जो 1981 और 1991 का अरसा था उस दौरान बहुत बड़े हादसे इस प्रदेश को झेलने पड़े थे । उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा यह जो देश में लोकतन्त्र है, जो इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र है, प्रजा का राज है, यह राज कोई बैसे मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ कांग्रेस के बड़े-बड़े चीटी के नेताओं ने दी थीं । हिन्दुस्तान के अनेकों शहीदों ने फांसी का फंदा चूमा था । फिर एक ऐसा राज्य आया, लोक-राज आया । उसके अन्दर हिन्दुस्तान के हर भाई बहन को चाहे वह महल में सोता हो, चाहे सड़क पर सोता हो, चाहे राजा और रक हो, सबकी बराबर का हक मिला । गाँव की पंचायत से लेकर लोकसभा तक अपने नुमायन्दे बनाने का हक सबको दिया गया । लेकिन 1981 से 1991 के बक्त में एक ऐसा दौर आया जब हरियाणा के अन्दर उस हक की छीना-झपटी हुई । हरियाणा के लोगों ने कुर्बानियाँ देकर उस हक को कायम रखा । कायम होने के बाद इस सरकार ने सबसे पहला काम इस प्रदेश को जो दिया वह दिया पूरी तरह से इस प्रदेश के अन्दर लोकतंत्र की ब्रह्मली का । जहाँ तक पंचायती राज को लागू करने की बात है आपको मालूम है कि नगर परिषद् के चुनाव आये तो सही तरीके से आजाद हरियाणा अस्तित्व में आया । पूरे तरीके से, प्रजातान्त्रिक तरीके से हरियाणा के सिस्टम को चलाया और बड़े ठीक

[श्री मनी राम]

तरीके से सारे प्रोग्राम इस प्रदेश में चलते रहे। चाहे महिलाओं के विकास करने की बात हो, चाहे पंचायतों को, नगर निगमों के अधिकार देने की बात हो और चाहे दूसरे नागरिकों को आगे लाने की बात है, वह सब हरियाणा में हुआ। जहाँ तक नौजवानों को रोजगार देने की बात है सरकार ने शानदार प्रोग्राम नौजवानों को रोजगार देने के लिए बनाया है और यह एक अच्छा तरीका है औद्योगिक विकास का। हरियाणा में औद्योगिक विकास का प्रोग्राम जो चला है इससे एक इन्डस्ट्रियल माहौल बना है। वह नौजवानों के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ है। आप अन्दाजा लगायें किस तरह से आज की सरकार ने, भजन लाल की सरकार ने पूरे तरीके से ऐसा सिस्टम रख दिया कि जो भी उद्योग लगे हैं उनमें उद्योगपतियों को हरियाणा के बच्चों को लगाना पड़ेगा। चाहे पांच बच्चे नौकरी पर लगे थे पांच हजार लेकिन हरियाणा के बच्चों को ही नौकरी पर लगाना पड़ेगा। तभी उसको लाईसेंस मिलेगा तथा दूसरी सुविधाएँ मिलेंगी। हरियाणा ही एक पहला प्रदेश है जिसने इस तरह की एक काम की बात यहां के नौजवानों के लिए की है। आपको याद होगा कि पंजाब हमारे पड़ोस का प्रदेश है और वहां दस साल तक उपजाव का दौर रहा, उसकी आग की हरियाणा को भी झेलनी पड़ी। एक पड़ोसी प्रदेश में जो भी अच्छी बुरी बात होती है उसका असर पड़ोस के प्रदेश पर भी पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप अन्दाजा लगायें कि हिन्दुस्तान के अन्दर किसी प्रदेश के मुख्य मन्त्री को, देश के या प्रदेश के किसी नेता को अगर किसी दुश्मन, उपजावदी या आतंकवादी संगठन से जान का खतरा है तो वह ज्यादा हमारे मुख्य मन्त्री जी को है। मुख्य मन्त्री जी ने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, कोई किसी की भैंस नहीं खोल रखी। इन्होंने प्रदेश में शान्ति लाने के लिए और गरीब किसानों को हक दिलाने के लिए जो कदम उठाये हैं तो यह इस बजह से विरोध है। भजन लाल ने किसी का विरोध नहीं किया फिर भी वे लोग इनके जानलेवा दुश्मन बने। पूरे तरीके से हरियाणा के मुख्य मन्त्री जी को इस बात का खतरा रहा। लेकिन उस वक्त भगवान की कृपा रही या गरीब लोगों का आशीर्वाद रहा कि यह प्रदेश ठीक चलता रहा। मैं यह अर्थ करना चाहूंगा कि सारे हरियाणा के अन्दर, सारे महकमों में चारों तरफ से चाहे किसान को भाव देने की बात हो, कोई भी यह नहीं कह सकता कि आज तक किसानों के भाव कम रहे हों। किसान की जिन्स हो, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, गेहूँ और गन्ना हो पूरे तरीके से जितनी किसान की मदद आज की सरकार ने की है उतनी किसी सरकार ने नहीं की। इसके अलावा बीज पर सबसिडी तथा और भी मदद खेतीहर भजदूर और खेतीहर किसान की सरकार ने की है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों बाढ़ आई, जो एक आम तरह से बारिश का पानी आता है, वह ऐसा पानी नहीं था। उस बाढ़ ने तो हरियाणा का पिछले 100 साल का रिकार्ड तोड़ दिया। बहुत ही भयंकर बाढ़ थी। वह जो बाढ़ आई वह कोई मामूली बाढ़ नहीं थी। तीन दिन तक लगातार बारिश बरसने से आधा हरियाणा प्रदेश

बाढ़ की चपेट में आ गया। यह बात ठीक है कि वह कोई मैन मेड बाढ़ नहीं थी। वह कुदरत का प्रकोप था। बाढ़ के दौरान हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी कभी ट्रैक्टरों पर बैठ कर सर्वे कर रहे थे, कभी पैदल चल कर सर्वे कर रहे थे और कभी हवाई जहाज से सर्वे कर रहे थे। कभी रात के 12:00 बजे मीटिंग कर रहे थे, कभी इरीगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों के ऑफिसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कभी बरवाला को ट्रैक्टर में बैठ कर देख रहे थे और कभी किशती में बैठ कर रोहतक शहर को देख रहे थे, वे लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए हर जगह गए। उसके बावजूद भी ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि वह फल्ट मैन मेड था। आप यह क्यों नहीं कहते कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर इससे पहले 100 सालों में भी ऐसी बाढ़ नहीं आई। बाढ़ के दौरान सरकार की तरफ से लोगों की फौरन मदद की गई। बाढ़ का पानी एकदम आ जाए तो उसको उसी वस्तु निकालने का कोई सास्ता नहीं होता। पानी तो नहरों के जरिए या नालों के जरिए ही जाएगा। कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां पर पानी को एकदम फेंका जा सके या उसको पम्प आउट किया जा सके। ऐसा प्रोग्राम तो दुनिया में कहीं भी नहीं है कि पानी को एकदम कहीं पर डाल दिया जाए। बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने और सभी मंत्रियों के ऑफिसरों ने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों को मदद पहुंचवाई। आप अंदाजा लगाएं कि जो मुआवजे की राशि आई वह राशि रेहड़ी वालों को, चाय के खोबे वालों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, किसानों और मजदूरों को मुआवजे के रूप में दी गई। उनको पांच हजार से बीस हजार ₹0 तक का मुआवजा दिया गया। इसी तरह से जिन खेतों में पानी खड़ा है उनका तीन हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया। आज तक किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया। यह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी की करामत है जिन्होंने गरीब किसानों की मदद की। यदि गरीब किसानों की भेद होती हो, यदि किसी जूता बनाने वाले गरीब की मदद होती हो, यदि किसी चाय बनाने वाले की मदद होती हो या किसी साइकिल का पंपचर लगाने वाले की मदद होती हो तो भाई राम बिलास शर्मा और दूसरे विपक्ष के भाईयों को बड़ी तकलीफ होती है। उनकी मदद सरकार ने की है वह इसलिये की है क्योंकि मदद करना हमारा धर्म बनता है। आपको इस बारे में सरकार को शाबाशी देनी चाहिये लेकिन आप ऐसा नहीं करते।

**श्री कितानब सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य ने रेहड़ी वालों को मुआवजा देने के बारे में कहा है, छोटे दुकानदारों को मुआवजा देने के बारे में कहा है कि उनको 5-5 और 10-10 हजार रुपए मुआवजे के दिए गए और बड़े दुकानदारों को 20-20 हजार रुपए दिए गए। मैं कहता हूँ कि गोहाता में जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा नहीं दिया गया।

**श्री 0. राम बिलास शर्मा:** डिप्टी स्पीकर साहब, मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि गोहाता में किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसी रेहड़ी वाले या दूसरे



[प्रो० राम बिलास शर्मा]

गरीब लोगों को कोई मुआवजा गौहाना में नहीं दिया गया। ये मुआवजा बांट रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर में। शमशेर सिंह मुख्तियारवाला के घर में इन्होंने रजार्डियों का डेर लगा दिया अगर उनमें आग लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

**श्री मनो राम :** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी राजा होता है वह एक बेईमानी को छिपाने के लिये 100 बेईमानी करता है। जी राजा ईमानदार होगा वह सही काम करेगा। जी मुआवजे को राशि बांटी गई उसकी वैरी-फिकेशन के लिये यहां चण्डीगढ़ से 5-5 सीनियर आई०ए०एस० ऑफिसर्स गए और उन्होंने उसकी पूरी वैरीफिकेशन की। यह कोई मामूली बात नहीं है यह एक ईमानदार राजा की निशानी है।

**प्रो० राम बिलास शर्मा :** डिप्टी स्पीकर साहब, इस महान सदन में कही गई एक बात का हरियाणा की जनता बड़ा नोटिस लेती है। चौधरी मनो राम जी केहरवाला ने कहा कि जूती गांठने वालों को और रेहड़ी लगाने वालों को मुआवजा दिया गया। यदि दिया गया है तो अच्छी बात है। किताब सिंह भल्लक जो कि गौहाना हल्के से पहली बार नहीं आए बल्कि दूसरी बार चुन कर आए हैं वे कह रहे हैं कि वहां पर रेहड़ी लगाने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि वे इन्हीं की पार्टी की सरकार को स्पॉर्ट कर रहे हैं। जो वे कह रहे हैं तो उनकी बात की सच माना जाये या मनो राम जी की बात को। ये एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। पानी के मामले में मैंने कहा कि फलां फलां गांव में और इतनी इतनी जमीन में पानी खड़ा हुआ है लेकिन अमीर चन्द मक्कड़ जी ने कहा कि सड़के तीन लाख एकड़ में पानी नहीं खड़ा। मैं चाहता हूँ कि हाउस का कोई सदस्य जब कोई बात कहता है तो उसका नोटिस लिया जाना चाहिये। ये कह रहे हैं कि मुआवजा दिया गया है और वे कह रहे हैं कि नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि मैंने भी शहजादपुर गांव के लोगों की 350 एप्ली-केशंस पर अपना डी०ओ० लेटर लगाकर चीफ सैक्रेटरी साहब को भेजा है कि इनको मुआवजा नहीं मिला।

**श्री मनो राम :** डिप्टी स्पीकर साहब, डबवाली कांड हुआ। यह कांड कुदरत की तरफ से हुआ और वहां पर स्कूल के 1200-1300 बच्चे और उनके अभिभावक इस दुर्घटना के शिकार हुए। यह घटना किसी शार्ट सर्कट की वजह से या किसी और कारण से हुई। जब यह घटना हुई तो मैं और चौधरी जगदीश नेहरा जी अपने अपने हल्के में थे। जब हमें पता चला तो हम डेढ़ घंटे के अन्दर अन्दर वहां पर पहुंच गए। यह सारी घटना वहां पर 2-4 मिनट में ही हो गयी। इस घटना के बाद सरकार की तरफ से और वहां की संस्थाओं की तरफ से शिकार हुए लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। जिन सामाजिक संस्थाओं ने इस में सहयोग दिया उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जब इस घटना का पता मुख्य मंत्री जी को चला तो ये भी फौरन

वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर मुख्य मंत्री जी पहुँचे तो मुख्य मंत्री जी ने 400-500 लोगों के सामने यह पूछा कि बताओ किससे इसकी इस्कवायरी करवाए। तो इनकी पार्टी के वर्कर्स जो थे उन्होंने कहा कि जिससे आपको ठीक तसल्ली हो सकती हो इस्कवायरी करवा ली। वहाँ पर 400-500 लोगों के अलावा मैं भी था, नेहरा साहब भी थे और दूसरे जिले के सारे साथी वहाँ पर थे। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में पता नहीं क्या मैनूप्लेयान हुआ कि दिल्ली से कुछ लोग आए। रात को वे दवाई आदि लेकर आए थे। जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से दवाई आदि लेकर आए हैं तो इनके लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मरीजों को लुधियाना, रोहतक और पी०जी०आई० आदि जगहों पर भेज दिया गया है। हमने दिल्ली से आए हुए लोगों को कहा कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं तो वे कहने लगे कि हमारे ठहरने का प्रबंध करा दीजिए। हमने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन सबेरे लोगों की लाशों को जलाने नहीं दिया गया और उनकी लाशों को यहाँ लाया गया था। डी०एस०पी० ने जिनकी शिताब्त नहीं हो सकी थी, उनकी लाश को वहीं रखने दिया जो मित लोग थे या उनके पैरेंट्स थे या उनके अभिभावक थे, वे दूसरे शहरों में घायल लोगों को लेकर गए थे। दूसरी बात जो वहाँ उन्होंने कही, वह बिल्कुल पोलिटिकली मोटीबेटिड प्रोग्राम था। हालांकि वहाँ पर 400-500 लोग जल गए। उनके घर वालों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी। जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वे कह रहे थे कि किसी का दोष नहीं था, कुदरत का दोष था। इस प्रकार से उन्होंने पोलिटिकली मोटीबेटिड प्रोग्राम बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य मंत्री महोदय ने मदद की, सरकार ने मदद की, मृतकों के परिवार वालों को एक लाख रुपये की मदद की। जो वहाँ खत्म हो गए, जिनका देहांत हो गया था उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो भी प्रोग्राम आज की सरकार या मुख्य मंत्री जी चला रहे हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वह "अपनी बेटी, अपना धन ही," चाहे शिक्षा का मामला हो या पिछड़े वर्ग का हो जिनमें लोध, सैनी, मेथ्रो आदि जातियों को बैकवर्ड क्लास में लिया गया है। यह एक अच्छा काम किया है। इस प्रकार से अब इनकी नौकरियों में लाभ मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे तथा अपना विकास करने के लिये इस क्लास को जो सुविधाएं दी गई हैं इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। स्वास्थ्य सेवाओं का जहाँ तक संबंध है इनमें भी काफी सुधार हुआ है। आज देहांत के अन्दर जो प्राईमरी हेल्थ सेंटर हैं, सी०एच०सी० हैं और डिस्पेंसिरियां हैं उनमें हर तरह से देहांत के लोगों को मदद मिल रही है। इस बात के लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने पिछले 5 सालों के अर्से में परिवहन सेवाओं में काफी नौजवानों को रोजगार दिया गया है। इसी तरह से कोआप्रेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, उनमें जो मैट्रिक पास लड़के हैं, उनकी 5-7 बच्चों की कोई सोसाइटी बना कर उनको रोजगार देकर अच्छा काम किया है। आम जनता को इस बात का काफी फायदा हुआ है और परिवहन के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था, इस पर राजेन्द्र ब्रिसला जी ने जो उनके सम्मान में धन्यवाद

[श्री मनी राम]

प्रस्ताव रखा इसके लिए मैं अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और मेरा सारे सदन से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद।

श्री० छतर सिंह चौहान (मुण्डाल खुर्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो हरियाणा की संवैधानिक सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिभाषण का पठन किया है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने और उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, भाषण में कहा गया है कि यह हरियाणा की आज की सरकार विधिवत रूप से काम कर रही है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर हरियाणा में सरकार रूल्स आफ ला के अनुसार कार्य करती लेकिन पिछले पाँचे 5 सालों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री बने हैं तब से रूल्स आफ ला वाली कोई बात नहीं दिखी। जब वे आए थे तो उन्होंने अपनी छाती ठोक कर इस सदन में एक बात कही थी कि इस तरह का प्रशासन हुआ कि हरियाणा की जनता यह कहेगी कि हर नर व नारी सम्मान से अपना जीवन बिता रहा है। हमें खुशी हुई थी जुलाई, 1991 में लेकिन इस 5 साल के समय में चौधरी भजन लाल की सरकार ने रूल्स आफ ला की जगह पर रूल्स आफ जंगल बना दिया है। आज ऐसा महसूस होता है कि हरियाणा में कोई राज नाम की चीज नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं है। न कोई राज है न कोई सरकार है। आज इस हरियाणा में अगर किसी चीज की बहुतायत है तो वह भ्रष्टाचार की है। आज का शासन और प्रशासन आकट रूप में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। शर्म से गर्दन झुक जाती है जब कोई मिलता है। हाईकोर्ट ने 1700 सिपाहियों की सेवाएं रद्द कर दी हैं। आज पटवारियों की सेवाएं रद्द कर दीं, आज इंस्पेक्टरों की सेवाएं रद्द कर दीं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि किसी प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री के सकेत पर इस्तीफा देना और उन्हें फिर किसी लाभ के पद पर आसीन करने का कार्य मुख्य मंत्री और सरकार की नीयत की बात साबित करता है। मुख्य मंत्री महोदय बताएं कि वह जो आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था या जो मैबर था अगर उनकी कार्याविधि ठीक थी तो क्यों उनको मजबूर किया गया कि वे इस्तीफा दें? अगर वे यहां ईमानदारी से काम नहीं कर सकते थे तो क्या उनको एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन लगाकर उसको भी भ्रष्टाचार बोर्ड बनाने के लिए वहां पर भेजा गया है। इसी प्रकार से 2 और सदस्य थे जिनमें से एक को तो गूंगरफंड का चेयरमैन बना दिया और दूसरे को कहीं और कुछ बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा तथा प्रार्थना करूंगा कि वे अपने जवाब में यह जरूर बताएं कि वेकॉन से हालात थे जिनकी वजह से मजबूर हो कर उन चार व्यक्तियों को इस्तीफा देने पड़े थे और फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनीं कि उनको लाभ का पद दे कर उनका मुंह बन्द करना पड़ा ताकि वे इनकी कारगुजारियों को हरियाणा की जनता के सामने न रख सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से



हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया है, वे जानते हैं कि जब भी मुख्य मंत्री जी कोई बात कहते हैं चाहे वे सदन में कहें या शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कहें, लोग मानते हैं कि हरियाणा का मुख्य मंत्री does not mean what he says. जो भी बात आज तक उन्होंने कही है वह पूर्ण नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनको याद होगा, मेरे हृदय में मुख्य मंत्री जी गए थे, इस बारे में भी मैं बताऊंगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1991 यानि जब से यह सरकार बनी है तब से ले कर आज तक का इतिहास उठा कर देख लें, किसी जिले या गांव में जाएं, तो आज की सरकार के मस्तिष्क पर कलक का टीका और काण्डों का टीका मिलेगा। चाहे बराही का काण्ड हो, चाहे नारनोद का काण्ड हो (विघ्न) वहां पर किसान बेचारे अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे हुए और इस सरकार ने उन पर दनादन गोसियां चलाई। कादमा का काण्ड हुआ। 23 अगस्त को बेचारे निर्दोष किसान अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां चौधरी भजन लाल की सरकार ने दनादन गोसियां चला कर 6 व्यक्तियों को हमेशा के लिए सुला दिया। इसी प्रकार से ये कहते रहे हैं कि नारी चाहे सोने की गठरी ले जाए, उसको कोई खतरा नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी अपने कामों पर थोड़ा दृष्टिपात करें। बहन सुशीला का काण्ड हुआ, जिसके बारे में सीधी उंगली आपके परिवार की तरफ उठती है। आपके निजी लोगों पर उंगली उठती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनमें हिम्मत है तो आज ये कहें कि इस केस में मेरा और मेरे किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं है। इसी प्रकार द्रोपदी काण्ड हुआ। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी यह बात कहता हूँ। मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ, या तो ये कान बन्द कर लेते हैं या इनका ध्यान सुनने में नहीं रहता। फिर भी मैं इस बात को रिपेट करता हूँ कि इस मामले में मेरे या मेरे किसी आदमी का हाथ होने का कोई सबाल ही नहीं है। ऐसी बात में हमारा हाथ होने की बात तो दूर हम तो सपने में भी इस प्रकार की बात नहीं सोच सकते।

श्री 0 छतर सिंह चौहान : यह तो सी 0 बी 0 आई 0 बताएगी ऐसे ही कहने से कोई बात 16.00 बजे नहीं बनती है। आपसे ऊपर भी एक लाकत ब्रेठी है और वह सब कुछ देख रही है। इस सरकार ने इतना मटमैला दाग छोड़ दिया है जिसको कभी भी कोई धो नहीं सकता है। अब ये कहते हैं कि हम विधिवत राज करते हैं, कल आफ ला के तहत सरकार चला रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त कितनी धांधली हुई थी। भिवानी के जुई गांव में एक भाई-बहन को मार दिया गया था। उनके हत्यारों पर मुकदमा चलाया गया था। कोर्ट ने तीन वाधमियों को छोड़ दिया था और तीन आदमियों को आजीवन कारावास की सजा दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, कितनी शर्म की बात है, उन आदमियों को 1994 में पैरोल पर छोड़ा गया उसके बाद फिर उनकी पैरोल की तिथि बढ़ा दी गई। 9 अप्रैल को उनको

[श्री० छत्तर सिंह चौहान]

वापिस जाना था लेकिन वे आज तक वापिस नहीं गए। उसके तीन महीने तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके बारे में 12 जुलाई को इस्तलाह दी गई लेकिन जेल सुप्रिन्टेंडेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके तीन महीने बाद तो एफ० आई० आर० दर्ज की गई। 12 जुलाई से दिसम्बर तक उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया। किसी आदमी ने देखा कि हरियाणा में तो जंगल राज चल रहा है तो उसने पब्लिक इंटैस्ट में हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। कोर्ट ने आर्डर दिए कि इस मामले में एस० पी० को खुद हाजिर होना पड़ेगा। इन चीजों के बाद भी मुख्य मंत्री जी कहें कि मेरे राज में मल आक ला है तो यह ये ही जानें। इसी प्रकार सिपाहियों की भर्ती के बारे में काफी जिंक किया गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि डी० आई० जी० श्री वी० एन० राय ने डी० प्रो० लिखा था कि डी० जी० पी० ने एक सिपाही की भर्ती के लिए 70 हजार रुपये लिए हैं। अगर 17 सौ का हिसाब लगाएँ तो यह 11 करोड़ 90 लाख रुपया होता है। मुख्यमंत्री जी के अपने बेटे चन्द्रमोहन जी इस सदन के सदस्य भी हैं, ने एक अखबार में मंजूर किया था कि अफसरों ने बहुत धांधली की है। पिछले सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी ने उनके घर में भर्ती के बारे में जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई आ गया होगा तो उसका नाम ले लिया होगा। ऐसा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था। यह बड़ी ही शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी आपको यह सब रोकना चाहिए; अगर ऐसा ही करेंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद आज तक 14 हजार पुलिस कमियों की भर्ती की गई है और 70 हजार रुपये एक आदमी के हिसाब से लगाया जाए तो यह 10.5 करोड़ रुपये बनता है जोकि इन्होंने पुलिस की भर्ती करने में ख़ाया है। पुलिस भर्ती में 10.5 करोड़ रुपये का इल्जाम इस सरकार पर लगा है। इसी तरह से एक्सट्रान एड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है। इसी तरह से नाजायज ढंग से तीन व्यक्तियों को एच० सी० एस० प्रमोट कर दिया गया, अगर एक एक व्यक्ति से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये लिए गए हैं।

**श्रीधरी भजत लाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट अफेयर आर्डर है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य किस किस किस के इल्जाम लगा रहे हैं, यह हमारी तो सभ्यता में नहीं आता। कभी ये कहते हैं कि 70-70 हजार रुपये ले लिए कभी ये कहते हैं कि पाँच-पाँच लाख रुपये भर्ती में लिए हैं। इनकी यह बात गलत है कि ये बगैर किसी सबूत के वगैर किसी आधार के इस तरह की बेवुनियाद बातें करें। जो इन्होंने 70 हजार या पाँच लाख रुपये के इल्जाम लगाए हैं तो या तो ये इनकी साबित कर दें वरना ये बातें हाउस की कार्यवाही से निकलवायी जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** चौहान साहब, अब आप बताएँ कि आप इन ऐसी गैरान को कैसे साबित करेंगे ?



**प्रो० छतर सिंह चौहान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिवाना चाहता हूँ कि इनके अपने ही लड़के ने अखबार में कहा है कि पुलिस की भर्ती में ऑफिसरों ने गड़बड़ी की है तो इसका क्या मतलब है ?

**श्रीधर भजन लाल :** यह मैंने भी अखबार में पढ़ा है। अखबार वाले रिपोर्टर ने वैसे ही यह छाप दिया होगा।

**प्रो० छतर सिंह चौहान :** मेरे पास यह नवभारत टाइम्स 25 फरवरी, 1996 का अखबार है।

**श्रीधर भजन लाल :** मैं आपको इस बारे में कल भी बताऊंगा और आज भी बता देता हूँ। वही नवभारत टाइम्स मेरे पास भी है। आप मेरी बात तो सुनिए। कल जो बंसीलाल जी ने कहा था कि चालीस हजार रुपये भर्ती में लिए गए हैं जब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। दिनांक 27-2-96 का नवभारत टाइम्स अखबार है, इसमें एक शीर्षक है कि—“अपार दर्द और गुस्सा छिपा है उनके दिलों में”। इसमें 1700 पुलिस कर्मियों की भर्ती के बारे में लिखा गया है। इसमें राकेश कुमार, सतबीर, राजकुमार, संजय, विनोद और सुनील के नामों का उल्लेख किया गया है। यह खबर रोहतक से निकली है। इन नामों के व्यक्तियों को 1995 में भर्ती किया गया था लेकिन जब उनसे और उनके परिवार वालों से पता किया गया कि क्या अपने पैसे दिए हैं तो सभी ने कहा कि भर्ती के लिए उन्होंने कभी कोई पैसा किसी को नहीं दिया है और न ही किसी अखबार वाले को उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। यह खबर प्रेस रिपोर्टर ने अपने आप ही मत गढ़त कहानी बनाकर लिखी है और इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस अखबार वाले से पूछा गया कि क्या उसने ईमानदारी के साथ यह खबर छपी है तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर नहीं गया और मैंने तो यह वैसे ही सुनी सुनाई बात लिख दी है। क्योंकि बंसीलाल जी ने रोहतक में बोलते हुए इस बारे में कहा था और हमने वही बात छाप दी है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

**प्रो० छतर सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, ये चन्द्रमोहन द्वारा कही गयी बात पर भी आए यह मेरे पास 26 नवम्बर, 1995 का अखबार है।

**श्रीधर भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं बंसी लाल द्वारा कही गयी कल की बात बता रहा हूँ कि पहले तो ये ऐसी ऐसी बातें छपवा देते हैं और फिर उन्हीं को यहाँ हाउस में लहराते हैं। इस बात का कोई मतलब ही नहीं है और न ही इसका कोई दावा मान है।

प्र० छतर सिंह चौहान : सर, ये चन्द्रमोहन द्वारा कही गयी बातों का भी जवाब दें।

### वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री चन्द्र मोहन द्वारा

श्री चन्द्र मोहन : सर, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो दत्ताल साहब और प्रोफेसर साहब ने कहा है वह बिल्कुल गलत बात है और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। जो ये कह रहे हैं इसके बारे में आप चाहें तो हाउस की भी एक कमेटी बनाकर इसकी इकवाथरी करवा सकते हैं। अगर मैंने यह नहीं कहा हो तो इनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिये और यदि मैंने कहा हो तो मेरे खिलाफ ऐक्शन होना चाहिये। इनको इसलिये मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्र० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास 26 नवम्बर का अखबार है और मैं आपको चन्द्रमोहन के द्वारा कही हुई बात के बारे में बता रहा हूँ।

श्री सुभाष बंतारा : स्पीकर सर, ये हर किसी पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंतारा साहब, आप बैठिए।

प्र० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही थी कि 1700 सिपाहियों की भर्ती में हरियाणा में गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ की स्वीकृति में माननीय सदस्य चन्द्रमोहन का मैंने नाम लिखा है। यह 26 तारीख का अखबार है। (घंटी) उन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि गड़बड़ी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) अगर यह झूठ है तो आप उस अखबार वाले पर मुकद्दमा चलाएँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आपको और कुछ बोलना है तो बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्र० छतर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा है। यह नवभारत अखबार में छपा है कि चन्द्रमोहन ने स्वीकार किया है।

(ओर एवं व्यवधान) में प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर बोल रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि आज हरियाणा की जनता इस बात का मान चुकी है कि इस प्रदेश में रूल आफ ला नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है, सरकार अष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। आज से दो साल पहले मैंने चुनौती दी थी कि मुख्यमंत्री जी आप अपना भेष बदलकर कालका से लेकर नारनौल तक जाएं। सारे हरियाणा की जनता यह कहती है कि मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं कि अष्टाचार शुरू तुम चले मैं गुरु। इनका प्रशासन यही करने में लगा है। यहाँ सिपाही बिकता है, एस०पी० बिकता है और थाने नीलाम होते हैं..... (विघ्न)

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, फिर ये वैसी बात करते हैं कि एस०पी० पैसा लेता है, थाने नीलाम होते हैं। इस किसम के आरोप लगाना मनासिब बात नहीं है। आप अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके इसे हाउस की कार्यवाही से निकलवाइए।

**प्रो० छतर सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे प्वाइंट पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। बाढ़ के बारे में बात आई। भिवानी जिले पर बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी। आज सरकार और उसके विधायक छाती ठोक कर यह बात कहते हैं कि हमने मदद की। जिस वक्त पानी आया हुआ था तो पटवारी से लेकर डी०सी० तक कोई गांव में नहीं दिखा। न दवाइयां थीं न राहत थी, अगर कोई राहत-कार्य था तो वह सारा काराजों में था। मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भिवानी गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने 34 लाख 51 हजार रुपये की भोजन सामग्री बंटवा दी है, 19 लाख रुपये के कपड़े बंटवा दिए हैं। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि किसी ऐजेंसी से जांच कराए अगर भोजन सामग्री नाम की कोई चीज गई हो। हाँ, कुछ पैकेट्स जरूर एक दिन गए थे जिसमें 5-7 दिन की फंफूद लगी हुई पूरी और थोड़ी सी सब्जी थी। अध्यक्ष महोदय, भोजन सामग्री बांटने में भारी गड़बड़ हुई है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जो राहत कार्य का मुआवजा बंटता उस को सरकार के मन्त्रियों ने और सरकार के विधायकों ने अपनी एक निजी सम्पत्ति बना लिया। यह बात मैं नहीं कहता बल्कि मेरे पास एक अखबार है उसमें लिखा है कि सफीदों के विधायक जो आज मंत्री भी हैं उन्होंने एक रवैया अपनाया था। वे अपने आदमियों को चिट देते थे। किसी चिट पर विशेष लिख देते थे और किसी पर अति विशेष लिख देते थे। वहाँ के एस०डी०एम० को आखिर यह सोचना पड़ा कि विशेष और अति विशेष में क्या अन्तर है। अगर ये इस बात से इन्कार करते हैं तो मेरे पास यह 26 तारीख का दैनिक ट्रिब्यून है, मैं इसको पढ़ कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि मुआवजे की सिफारिश करने में स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री बचन सिंह आर्य ने अपने समर्थकों को विशेष और अति विशेष दो वर्गों में बांटा। जब सभी को अति विशेष की संज्ञा देने लगे तो एस०डी०एम० ने अपने हाथ उठा लिए।

## वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

आवास राज्य मंत्री द्वारा

आवास राज्य मंत्री (श्री बचन सिंह श्याम) : सर, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने मेरे हल्के का जिक्र किया और मेरी चिट के बारे में जिक्र किया। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री और इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सफ़ीदों के हल्के में सरकार ने 16 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिये भेजा। उसके लिये इलाके के लोग इतने खुश हैं कि जिसका कोई अन्त नहीं। इनकी पार्टी के लोग वहाँ गए थे। जब फ्लड आया तो उस समय जो राहत कार्य हो रहे थे उस समय ये लोग अपनी पत्नियाँ बनाकर ले आए थे। वह मेरे पास रखी हुई हैं। ये अपनी विकास पार्टी की चिट लगाते थे। इन्होंने रोडियों पर भी चिटें लगाई।

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, अगर इन्होंने इस तरह की चिट दी है तो वे लोग तो उसे पढ़ेंगे ही जिनकी दी है। वे देखेंगे कि एक चिट पर यह लिखा है और दूसरी पर यह लिखा है। अगर ऐसा है तो वह तो वैसे ही इनके खिलाफ बात हो गई।

श्री बचन सिंह श्याम : मैंने सारे हल्के में कोई भी इस तरह की चिट नहीं दी। आप अखबार की ऐसे बात कह रहे हैं जैसे सारी ही बातें इसमें सच्व लिजी हों। मैंने अपने हल्के के 65 गांवों में राहत के मामले में पार्टी बाजी की कोई बाल नहीं की। हमने सब की बराबर समझा। ये देख लें कि इनको आने वाले चुनावों में उस हल्के से अपनी अमानत जबत करवानी पड़ेगी।

## राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराखण्ड)

श्री 0 अतर सिंह चौहान : माननीय राज्यपाल महोदय ने पैरा 7 में कृषि के बारे में बताया है। हमारा हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इस बार जो बाढ़ आई उसने किसानों की कमर तोड़ दी। उसके बाद बाढ़ का मुआवजा बांटने में जो प्रक्षपात हुआ वह निन्दनीय है। अगर बाढ़ आई थी तो वह परमात्मा की भार थी। मैं तो यह कहता हूँ कि प्रकृति की भार से ज्यादा सरकार के मन्त्रियों ने ज्यादा भार मारी। मेरे हल्के में कोई बाढ़ नहीं थी। स्पीकर साहब, चार सितम्बर को बारिश बन्द हो चुकी थी। यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री बहन करतार देवी जो कलानीर से हैं, इन्होंने सात तारीख को रेलवे पुल कटवा कर हमारे इलाके को डुबो दिया। चार सितम्बर के बाद बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी? फिर श्री आनन्द सिंह डांगी ने अपना घर, अपना गांव बचाने के लिये मीखरा गांव को डुबो दिया। बतरा साहब ने अपना घर, अपनी कोठी बचाने के लिए रोहतक शहर को डुबो दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्रियों का ऐसा अभिभाषण

हैं तो इस सदन के व्यक्तियों से क्या अपेक्षा करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात की हार्ड कोर्ट के जज से जांच हो। (विघ्न)

श्री सुभाष बतरा : स्पीकर साहब, मैं एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले भी वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

श्री सुभाष बतरा : सर, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ।

श्री 0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच किसी हार्ड कोर्ट के जज से कराये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। वे आदमी आज मुखौटा पहनकर बात बनाते हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को डुबोने में और इसके विनाश के लिए एक अहम भूमिका निभाई।

### वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

गृह राज्य मंत्री द्वारा

श्री सुभाष बतरा : सर, मैं पर्सनल एकस्प्लेनेशन देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब इन्हें कहने दो, इनका निजी स्पष्टीकरण है।

श्री सुभाष बतरा : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या इनको कोई लाईसेंस दे रखा है कि सुबह से लेकर अब तक सारी निराधार बातें कहते रहें। जो सारी बातें इन्होंने कही हैं जैसे मेरे सिक्योरिटी गार्ड वाली बात कही। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें निराधार, झूठी और बेबुनियाद हैं।

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, यह बात नई नहीं है पिछले सत्र में भी इन्होंने कहा था कि हमारी नहर काट दी। अध्यक्ष महोदय, जिस रेलवे लाइन की ये चर्चा कर रहे हैं, वह भिवानी से आती है। जो हाउस में मेरे रोज यह कहा करते थे कि आप अपनी बात को पुट करिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह रेलवे लाइन भिवानी से खरक और खरक से कलापीर होकर जाती है। अगर इस लाइन को कटवा देते तो पहले मेरा ही हल्का डूबता, इनका इलाका तो बाद में आता है। जो ये कह रहे हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोखना चाहिए। (विघ्न)



प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चुनौती देता हूँ कि आप किसी हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करा लें कि सात सितम्बर की शाम के तीन बजे बहन करतार देवी, कक्षानौर का शानेदार और बी०डी०ओ० वहाँ नहर को काटने को और कटवाने को तत्पर थे या नहीं। परन्तु वहाँ पर हजारों लोग तैनात थे इसलिये इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये सब गलत बोल रही हैं ..... (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार के बारे में बोलते हुए कहा है कि वह एस०वाई०एल० कैनल बना नहीं सकी। जिस दिन से मुख्य मन्त्री ने शपथ ली थी उसी समय उन्होंने कहा था कि एक साल के अन्दर एस०वाई०एल० पूरी करवा देंगे छः महीने में पूरी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा डिस्-क्रेडिट आज के मुख्य मन्त्री को जाता है। स्पीकर साहब \* \* \* \* \*

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाये।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बार बार आश्वासन दिया है कि हम एस०वाई०एल० बनायेंगे। जबकि पाने पांच साल का समय खत्म हो चुका है परन्तु एक इंच तक भी नहीं लगी, एक कस्ती भी यहाँ नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला है वह सिर्फ हरियाणा के लोगों की आँखों में धूल डालने के लिये किया है। (घन्टी) ये पहले भी एक बार इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गये थे। फिर इन्होंने वह वापस ले लिया। आज क्या जरूरत थी कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर गये हैं। सिर्फ इस बात के लिये कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये और कोई दूसरा तरीका इनके पास नहीं था। एस०वाई०एल० कैनल यह सरकार नहीं बना सकती क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। इनको अपनी कुर्सी का डर है। कम से कम यह सरकार यह तो कर दे कि हरियाणा प्रदेश के पास जितना पानी अवेलेबल है उसको दक्षिणी हरियाणा और झरे प्रदेश में बराबर बाँट दे। आज सिरसा और हिसार जिलों की नहरें महीने में 24 दिन चल रही हैं। महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। स्पीकर साहब, नहरें बनाना तो दूर रहा अगर इनमें हिम्मत है तो हरियाणा में जो मौजूदा पानी अवेलेबल है उसको सारे प्रदेश में बराबर बाँट दें। हिसार और सिरसा जिलों के अलावा जो दूसरे जिलों के लोग हैं वे भी तो हरियाणा के वासी हैं। यह नहीं होना चाहिए कि आज हरियाणा

\*नेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल बन गए तो वे रिवाड़ी, भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों के लोगों का विनाश करें। ये उन जिलों के लोगों का विनाश करने पर तुले हुए हैं। उन जिलों के लोगों का पानी का जो हक है वह उनको मिलना चाहिए। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आप मुझे अपनी बात कम्पलीट करने के लिये पांच मिनट का टाइम दे दें। मैं पांच मिनट में अपनी बात कम्पलीट कर दूंगा। हमारे प्रदेश में बिजली का बहुत बुरा हाल है। जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इस सीट पर बैठते थे तो कहा करते थे कि भजन लाल की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी क्योंकि इन्होंने बार बार बिजली की दरों को बढ़ाया है। लेकिन आज उनके ऊपर बिजली मन्त्री का भार है इसलिये आज वे यह बात कहने में लाचार हैं क्योंकि इनको अपनी कुर्सी जाने का डर है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में जितनी भयंकर स्थिति बिजली की है उतनी पहले कभी नहीं हुई। बिजली की कोई कमी नहीं है। (शोर)

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। लोगों ने इनको इलैक्ट करके यहाँ भेजा है। इन्होंने अपनी काल अटैशन मोशन के जरिए बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा। जब एक घंटे का सेशन का ब्रेक हुआ उस समय मैंने यहाँ से जाते ही खाना भी नहीं खाया मैंने एस० ई० भिवानी को टेलीफोन किया और मैंने उनको चार गांवों के नाम बताए कि बाँद, बढेसरा, मिश्री और बापीडा में जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको बदला क्यों नहीं गया। स्पीकर साहब, एस० ई० भिवानी ने और और यह कहा कि इन गांवों में एक भी ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ महीने से ट्रांसफार्मर बदलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 24 घंटे के नोटिस में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदल देते हैं। इनको इस तरह से गलत बात नहीं कहनी चाहिए।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। मैं कल इनके ऑफिस में जाऊंगा। मेरे सामने से एस० ई० भिवानी को टेलीफोन करें अगर वह मेरे सामने यह बात कह दें कि उन गांवों के ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिये छतर सिंह उनके पास बार बार नहीं गया तो मैं भान जाऊंगा। मन्त्री जो को इस तरह से असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह इनको शोभा नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप कल मेरे ऑफिस में क्यों आए अभी चलते हैं। यहीं से आपके सामने मैं भिवानी के एस० ई० से इस बारे में बात करता हूँ।

श्री मनी राम : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। एक दिन की बात है मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के पास अपने इलाके की बिजली की हालत बताने के लिये गया। उस समय प्रो० छतर सिंह चौहान हजूरवाला अपने हाथ में एक पची ले कर चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के पास आए। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इनको कहने लगे आओ चौहान साहब पहले आपका काम करेंगे। चौहान साहब कहने लगे कि यह एक जे० ई० को तबादला करना है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह तो कर देंगे आप बिजली की स्थिति के बारे में बताएं कैसे है। चौहान साहब कहने लगे कि वाकई में बिजली की स्थिति ठीक है लेकिन यह बात मैं असेम्बली में नहीं कहूंगा। (शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैंने इनसे किसी के तबादले की बात नहीं कही।

श्री मनी राम : इन्होंने उस समय यह कहा था कि मैं इसको असेम्बली में नहीं कहूंगा लेकिन वाकई में बिजली की स्थिति ठीक है। यह बात इन्होंने उस दिन कही थी।

Mr. Speaker : The position has already been clarified by the Minister about electricity. क्या इन्होंने यह भी कहा था कि बिजली ठीक चल रही है।

श्री मनी राम : स्पीकर साहब, इन्होंने यह बात कही थी कि बिजली ठीक सप्लाय की जा रही है लेकिन वह इसकी असेम्बली में ही नहीं करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह कोई बुरी बात नहीं है, जब ये मंत्री बन जाएंगे उस समय मैं इनके पास तबादले के लिये चला जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि ये दो महीने में होम मिनिस्टर बनेंगे। (हंसी)

प्रो० छतर सिंह चौहान : चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी आप ही बता दें कि क्या मैं आपके पास किसी तबादले के लिये जावा था।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का गसत ट्रांसफर हो जाये तो उस बारे में आप आकर कह सकते हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है।

श्री 0 छतर सिंह चौहान : आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हरियाणा में बिजली की बहुत अधिक चोरी हो रही है। इस चोरी को रोकने के लिये सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। (विन्त) इस बिजली को बड़े-बड़े कारखाने वाले चुरा रहे हैं और यह सब सरकार की शह पर हो रहा है।

स्पीकर साहब, जहाँ तक एजुकेशन का संबंध है, हमारे यहाँ पर अब एजुकेशन का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। आज एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। आपका तो एजुकेशन से संबंध रहा है और हम भी उससे जुड़े हुए हैं। इस बारे में सरकार और विभाग सिर्फ मार्च के महीने में सचेत होता है और वह भी नकल रोकने के लिये सचेत होता है। एक सिपाही से लेकर एस०पी० तक और एक पटवारी से लेकर डी०सी० तक और विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब सचेत होते हैं कि नकल नरोकें। अच्छी बात है नकल नरोकें। नकल होना हमारे प्रदेश पर एक कलंक है। मैंने सदन के पटल से कई बार कहा है कि शिक्षा के बारे में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे स्कूलों में ठीक प्रकार से पढ़ाई हो सके। आज देहात में बच्चों की ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। न वहाँ पर अध्यापक हैं और न कमरे हैं। मुलाना साहब के बच्चे तो शहर में अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन देहात के बच्चों की ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इसको गंभीरता से ले और देहात में बच्चों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दे। सरकार को चाहिये कि अध्यापकों का ठीक तबादला हो और उनकी ठीक तरह से नियुक्ति हो। जब उनकी नियुक्ति ठीक नहीं होगी तो वे पढ़ाई भी ठीक प्रकार से नहीं करवा पाएंगे। अतः मेरी पुनः मांग है कि इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे।

स्पीकर साहब, जहाँ तक परिवहन व्यवस्था का संबंध है, हमारे यहाँ पर वह भी ठीक नहीं है। किसी बस की छत ठीक नहीं है; किसी की खिड़की ठीक नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बसों के आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दो-तीन साल पहले मिनी बसों की खरीद के बारे में मैंने सवाल किया था। उस समय यहाँ पर बताया गया था कि इन बसों की ठीक प्रकार से खरीद नहीं हुई और इसमें चौडाला साहब और उस समय के परिवहन मंत्री को दोषी पाया गया था लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कृपया मुख्यमंत्री जी बताएँ कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ। जो पीने का पानी गांवों में दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है। हमारे नेता बंसी लाल जी ने भी कहा था कि कहीं का भी पानी टेस्ट करना लें वह पोटैबल

[श्री० छतर सिंह चौहान]

वाटर नहीं है। बेचारा गरीब किसान तो जोहड़ के पानी को भी हज्म कर लेता है लेकिन उनको पानी ठीक देना भी तो सरकार का कर्तव्य है। उनको गन्दा पानी दिया जा रहा यह कोई अच्छी बात नहीं है। उनको गन्दा पानी क्यों दिया जा रहा है क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी? मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर और सब डिवीजन पर कोई लैबोरेटरी हो। मैं तो यह कहता हूँ कि जहाँ भी वाटर बर्कस हो वहाँ पर लैबोरेटरी होनी चाहिये ताकि तत्काल पानी का निरीक्षण हो सके और लोगों को गन्दा पानी पीने से बचाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहब एक दो लाइन और कहूँगा। यह सरकार जब से आई है ला एंड आर्डर बिगड़ा है। सड़कों की बुरी हालत है। हमारे नेता चौ० अमर सिंह यह कहा करते थे कि सड़कों पर थैली नहीं लगेगी, नये पुल बनाए जाएंगे। अगर चौ० भजन लाल जो इन्हें जाकर देखें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी एप्रोच रोड पर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने कोई काम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

श्री० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

### नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a notice from Hon'ble Parliamentary Affairs Minister regarding holding of sitting concerning official business tomorrow i.e. 29th February, 1996. I have given my consent to move such a motion.

Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of [Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 29th February, 1996 from 9.30 A.M. to 1.30 P.M.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 29th February, 1996 from 9.30 A.M. to 1.30 P.M.

नियम 22(2) के अधीन कार्य के कार्यक्रम में परिवर्तन करना/राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को स्थगन करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेना

(4)37

**Mr. Speaker :** Question is—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Govt. Business be transacted on Thursday, the 29th February, 1996 from 9.30 A.M. to 1.30 P.M.

*The motion was carried.*

**नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव**

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, as per the decision of the House, Supplementary Estimates for the year 1995-96 are to be taken up today and it has been decided by the House to hold an official sitting tomorrow. In view of this fact, notice of another motion by Parliamentary Affairs Minister has been given for postponement of discussion on Governor's address to tomorrow so that demands for grants are discussed and voted today. I have given my consent for moving such a motion.

Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 22(2).

**Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) :** Sir, I beg to move—

That the discussion on Governor's Address be postponed till Thursday i.e. 29th February 1996 in favour of discussion and voting on the Supplementary Estimates 1995-96.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the discussion on Governor's Address be postponed till Thursday i.e. 29th February, 1996. In favour of discussion and voting on the Supplementary Estimates 1995-96.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the discussion on Governor's Address be postponed till Thursday i.e. 29th February, 1996 in favour of discussion and voting on the Supplementary Estimates 1995-96.

*The motion was carried.*

**नियम 22(2) के अधीन कार्य के कार्यक्रम में परिवर्तन करना/राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को स्थगन करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेना**

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now discussion and voting on the Supplementary Estimates for the year 1995-96 will take place. (Interruptions).



चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, आज सुबह यह तय हुआ था कि डिमाण्डज के ऊपर कल बोलना जाएगा, कल जब मुख्य मन्त्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे देंगे उसके बाद डिमाण्डज ली जाएगी। (विघ्न) यह आज के लिये नहीं था। (विघ्न) अगर आप अपनी बात से मुक़रते हैं तो आपकी मर्जी है। तब यह हुआ था कि यह कल होगा और आज गवर्नर एड्रेस डिस्कस होगा। (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है यह तय हुआ था कि बोलने का टाइम और बढ़ा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटे का लान्च ब्रेक करके दोबारा मिल लेंगे इसमें कोई बात नहीं है। जो बोलने वाले हैं वे घंटा दो घंटे और बोल लें, इसमें कोई नुकसान नहीं और उसके बाद डिमाण्डज आज ही जाएं। गवर्नर एड्रेस पर बहस का जवाब मैं कल दे दूंगा। उसके बाद नान-ऑफिशियल के शुरू हो जाएंगे यह फैसला हुआ था। यह तो रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने कहा था कि ठीक है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही निकाल लें, पता चल जाएगा।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहता हूँ कि आप कार्यवाही निकालवा लें, हम को भी पता है। हम भी उस वक़्त यहीं हाउस में थे हमको सब कुछ पता है। हम भी सदन में बैठे हुए थे। आप कार्यवाही देख लें। यह तय हुआ था कि आज शाम तक गवर्नर एड्रेस पर बहस हो जाए।

श्री अध्यक्ष : हमारी नालेज में तो यह बात है कि यह तय हुआ था कि डिमाण्डज आज हों।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, ऐसा तय नहीं हुआ था। आप कार्यवाही निकालवा लें। हम उसको सुन कर ही मानेंगे कि ऐसा तय हुआ था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये बोलना तो शुरू करें (विघ्न)

श्री० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रेस को कम्पलीट करवा दें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : वह सारी बात तो पहले ही ली है।

चौधरी बंसी लाल : नहीं हुई है।

चौधरी भजन लाल : अब तो दूसरा मोशन आ चुका है।

नियम 22(2) के अधीन कार्य के कार्यक्रम में परिवर्तन करना/राज्यपाल (4) 39  
के अभिभाषण पर चर्चा को स्थगन करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेना

चौधरी बंसी लाल : इस प्रकार का मोशन लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, आप बहुत ही पुराने और सीनियर मੈम्बर हैं और सब बातें जानते हैं। जब दूसरा मोशन आ गया और पास भी हो लिया तो अब क्या होना चाहिए। आप इस बारे में पहले कहते।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात प्रिसिपल की है न कि इस बात की है कि क्या है या क्या होना चाहिए। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह हो गया था वह ही गया। इनकी मर्जी है चाहे जो मोशन ले आए और उसको पास कर लें क्योंकि इनका बहुमत है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी वही कहना है जो मुख्य मंत्री जी कहेंगे। आप सवेरे की प्रोसीडिग निकलवा लें तो पता चल जाएगा कि आज सवेरे क्या तय हुआ था।

चौधरी भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी, आपको यह बात शोभा नहीं देती कि आप यह कहें कि जो मुख्य मंत्री जी कहेंगे वही आप कहेंगे। अगर ऐसा होता तो आज डेढ़ बजे ही सेशन खत्म हो सकता था लेकिन हमने कहा कि नहीं। (विधन)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें प्रोसीडिग पढ़ कर सुना दें, हम मान लेंगे या फिर गवर्नर एंड्रेस पर बहस चालू रहने दें।

चौधरी भजन लाल : जब अगला मोशन आ गया तो फिर वह बात तो खत्म हो गई। आपने "यस" कहा था मैंने खुद सुना है। (विधन)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिग पढ़ कर सुना दें, इसमें क्या दिक्कत है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है (विधन)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, ऐसा है कि प्रोसीडिग देखने गए हैं, उसमें अभी थोड़ा टाईम तो लगेगा।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरी भी सबमिशन है कि आप इस आगस्ट हाउस के गार्डियन हैं और आप कभी भी अपनी डिस्ट्रिक्शन लागू कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह डिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, गवर्नर एंड्रेस पोस्टपोन हुआ है।

श्री 0 राम खिलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरी सबमिशन यह है कि कुम्भा मार व्याह और पशु मार खेती कभी नहीं फलती। अध्यक्ष महोदय, अब पांच बजने वाले हैं और 1057 करोड़ रुपये की डिमांडज कम्प्यूटराइज्ड वे से पास कर दी जाएं। अगर ऐसा हुआ तो यह न्याय नहीं होगा। मुख्य मन्त्री जी ने अपने हंग से सारी बात कह दी क्योंकि आज अखबार वालों की छुट्टी है हमारे मुख्य मन्त्री जी का तो जवाब ही नहीं वे तो सारी बात पहले ही पता कर लेते हैं। इन्होंने कल जवाब देना है क्योंकि इनकी बात आज छपनी नहीं है स्पीकर सर, मैं आपसे सबमिशन करना चाहता हूँ कि 2-3 साथी गवर्नर एड्रेस पर बोलना चाहते हैं उनको थोड़ा बोलने दें। जैसे कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा है वे कल क्वेश्चन आबर के बाद गवर्नर एड्रेस पर रिप्लाई दे देंगे और उसके बाद डिमांडज के ऊपर चर्चा होगी। इसीलिए नेहरा जी नौन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में बदल रहे हैं। स्पीकर सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। (विघ्न)

सिन्हाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : अन ए प्वायंट आफ ऑर्डर। स्पीकर साहब, जो पहले मोशन आई वह रुल 30 के तहत नान ऑफिशियल को ऑफिशियल डे करने के लिये थी और दूसरी गवर्नर एड्रेस पर बहस को पोस्टपोन करने के बारे में थी। जब दोनों मोशन पढ़ी गई तो इन्होंने न भी नहीं की और जब ये एड्रेस हो गई हैं तो ये बोल रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात के लिये हां की थी कि नान ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाए। मगर इसके लिये नहीं की थी, ये डिमांड 1057 करोड़ रुपए की है। ये डिमांड नहीं पूरा बजट का बजट है। इस बारे में सुबह कहा गया था कि पूरी बहस होगी। अगर ऐसा नहीं कहा गया तो आप आज सुबह की कार्यवाही पढ़ कर सुना दें, अगर हम गलती पर होंगे तो हम माफी मांगेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह पैसा अगले साल के लिये नहीं है बल्कि पहले खर्च हो गया है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी आप यह सुनें जो आपने मानी है और आपने हां भरी है : This is as under :—

"That the discussion on Governor's Address be postponed till Thursday i.e. 29th February, 1996 in favour of discussion and voting on the Supplementary Estimates 1995-96."

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि आपने हमें बगैर कान्फीडेंस में लिये यह पास कर दिया। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह आखिरी सेशन है और हम यह नहीं चाहते कि हमारे से कोई मੈम्बर खफा हो या किसी को तकलीफ हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कुछ चाहते होते तो आज की सिटिंग डेढ़ बजे खत्म कर सकते थे। अध्यक्ष महोदय, अब कल नान आफिशियल डे नहीं रहेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल साढ़े दस बजे मेरा जवाब हो जाएगा और इसके बाद डिमान्डज ले लेंगे।

भावाज : ठीक है।

चौधरी भजन लाल : ठीक है, अब यह मामला खत्म हो गया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी मੈम्बर थोड़ा-थोड़ा बोल लेंगे तो हमारे कुछ मੈम्बर रहे गए हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कल 10.30 बजे मेरा जवाब आ जाएगा और उसके बाद डिमान्डज आ जाएंगी और नान आफिशियल डे खत्म हो जाएगा क्या आपको यह मन्जूर है।

चौधरी बंसी लाल : ठीक है।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the motion under Rule 22(2) carried by the House regarding postponement of discussion on Governor's Address be treated as withdrawn ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The motion under rule 22(2) is withdrawn.

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब श्री श्रीम प्रकाश जितन्दल गवर्नर एड्रेस पर बोलेंगे।

श्री श्रीम प्रकाश जितन्दल (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कानून और व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और कोई भी आदमी आज हरियाणा में सफ नहीं है। हिन्दुस्तान में कहीं भी इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से अफ़्गानिस्तान में भी हरियाणा सबसे आगे है। यहाँ पर पटवारी से लेकर डी० सी० तक सिपाही से लेकर एस० पी० तक और विधायक से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सभी ने बँड़ा मर्क किया हुआ है। इतना अफ़्गानिस्तान में फैला हुआ है . . . . (गोर एवं व्यवधान)

सिवाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आईर है। सर, माननीय सदस्य जित्दल साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह क्या इनको शोभा देता है? ये खुद ही सोचें कि क्या इस सभा में इनकी ऐसी-ऐसी बातें कहनी चाहिए। क्या ये बातें कोई कहने वाली हैं? (विघ्न) इनका यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री ओम प्रकाश जित्दल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यह इसलिये कह रहे हैं क्योंकि इनके पास पावर बहुत है। (विघ्न) अभिभाषण में वाढ़ के बारे में जिक्र किया गया है मैं तो यह कहता हूँ कि वाढ़ आने से इनकी तो लाटरी ही खुल गई है। जिसको रीयल में टुक मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं और सक्शियों एवं आफिसर्स ने अपनी लाटरियां इस वाढ़ में खोल ली हैं। जिसके सकान गिरे नहीं, जिसके पगू मरे नहीं उसको तो मुआवजा दे दिया गया लेकिन जिसको असल में मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया गया। इसी तरह से एस० वाई० एल० के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि मैं एस० वाई० एल० का पानी हरियाणा में ला दूंगा और अगर नहीं लाया \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* इस सरकार को बने हुए आज तीन महीने कम पांच साल हो गए हैं। (विघ्न)

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इनके द्वारा यह कहना कि नाक कटा लेंगे क्या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? अगर कोई इनकी ही ऐसा कहे कि आप अपनी नाक कटा लो तो इनकी कैसा लगेगा? माननीय सदस्य जो लैंग्वेज बोल रहे हैं क्या वह पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आती है। आप इनसे कहिए कि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज न बोलें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जित्दल साहब ने जी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कही है उसको रिकार्ड न किया जाए। जित्दल साहब आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही बोलें।

श्री ओम प्रकाश जित्दल : स्पीकर सर, इन्होंने विधान सभा के पहले ही सेशन में कहा था कि मैं एस० वाई० एल० का पानी ला दूंगा लेकिन इस काम में आज एक भी ईंट नहीं लगी और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अगर मुख्यमन्त्री जी इस मामले को लेकर अनशन कर देते और अनशन पर बैठ जाते तो पानी हरियाणा को मिल सकता था क्योंकि प्राईम मिनिस्टर इनको कभी भी मरने न देते और इनकी पूरी स्पॉर्ट वे करते हैं तो कहेंगे कि अभी भी टाइम है इसलिये ये अनशन पर बैठ जाएं। अगर ये एक महीने अनशन पर बैठ जाते तो दो करोड़ लोगों को इसका फायदा होता

वैसे भी श्रष्टाचार में इनका नाम ऊंचा है और अगर ये ऐसा करेंगे तो इनका कुर्बानी में भी नाम ऊंचा हो जाएगा। पैरा-7 में बिजली के बारे में जिक्र किया गया है। आज हरियाणा में जितनी बिजली पैदा हो रही है उसका 18-20 या 27 परसेंट के करीब लीस में जा रहा है। मैं कहता हूँ वह लीस नहीं है वह हेराफेरी है और वह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बेची जा रही है। (विघ्न)

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्लायंट आफ आर्डर है। क्या ये खुद समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं ? इनकी बात का कोई मतलब नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको कंटेन करिए कि जो भाषा बोलें वह ऐसी भाषा बोलें जो कि सभा के मुताबिक ही।

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब आप बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश जिंदल : बिजली ऐसी चीज है जिसमें 2-4 परसेंट का लीस तो हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा लीस नहीं हो सकता। किसान को बिजली सबसे कम मिलती है। किसान को चार घंटे बिजली मिलती है और बिल हार्स पावर के हिसाब से लिया जाता है। पैरा नं० 20 में एक परिवार एक रोजगार का जिक्र है, यह सही नहीं है चार घरों में एक आदमी को रोजगार भी नहीं मिला। बैंकवर्ड लोगों को भी सबसे कम मिल रही है। उनका भी पूरा हक है और हरियाणा में उनको भी सबसे मिलनी चाहिए। हरियाणा के हमारे जो हरिजन भाई हैं उनको भी सबसे मिलनी चाहिए। उनके पास पैसे नहीं हैं और बगैर पैसे के सबसे मिलती नहीं है। इसके अलावा जो 1700 सिपाही घर वापस आ गए हैं, उनसे जो रुपये लिए गए हैं, क्या वे वापस किए जाएंगे ? यह विश्वास दिलाएं।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इनको तो कोई फीबिया हो गया है और ये कुछ नहीं करेंगे। हरक बात के साथ मंत्री और मुख्यमंत्री इन्होंने जोड़ देता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बोलें तो ठीक ढंग से बोलें। यदि बोलना नहीं आता तो बोलना कोई जरूरी नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जिन्दल साहब, बार बार रेपीटीशन की जरूरत नहीं है और कोई बात कहनी हो तो कहें।

श्री ओम प्रकाश जिंदल : स्पीकर साहब, मेरी कोई ऐसी डायरी नहीं है जिस पर पैसे लिखे हों। जैन की डायरी में कोई भी प्लायंट छिपा नहीं 17.00 बजे निकला। हवाला कांड का उस ने पर्दा फाश किया है। धन्यवाद।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत मेहरबानी कि आने मुझे समय दिया। जिन्दल साहब ने अपनी झायरी के बारे में बताया। अगर वे अपनी झायरी खोल देंगे तो वह बाँध सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और पता नहीं फिर किस किस को मुश्किल होगी।

श्रीधरजी भजन साहब : उससे तो चौधरी बंसी लाल को मुश्किल हो जाएगी (हंसी)।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारे आदरणीय सदस्यों ने इस बारे में विस्तार में कहा है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस प्रदेश के अन्दर जो रक्षक हैं वही भक्षक हो रहे हैं। आज एस० पी०, डी० एस० पी० और इन्स्पेक्टर जेलों में बन्द हो रहे हैं तथा बहुत जल्द और भी होने वाले हैं। जहाँ ऐसी हालत हो तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहा जाए। जो लोग लोगों को जेल में बन्द करते हैं वे खुद जेल में बन्द हों तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा। मैं इस बात से आगे यह कहूँगा कि यहाँ पर चोरी, डकैती और रेप की घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इन पर कन्ट्रोल करना चाहिए। जहाँ तक बाढ़ का सवाल है इस बारे में पिछले सेशन में भी बात आई थी। उस समय तो केवल एक ही विषय पर बात हुई थी लेकिन अब दो विषय बन गए क्योंकि अब इस बाढ़ का मुआवजा भी उसमें शामिल हो गया है। प्रकृति का प्रकोप तो था ही लेकिन साथ में सरकार का प्रकोप भी बढ़ गया। अगर सरकार चाहती तो इस प्रकोप को भिवानी के अन्दर कम किया जा सकता था। उसके तीन कारण थे जिसकी वजह से वहाँ बर्बादी हुई। एक तो वहाँ सीवरेज की सफाई नहीं की गई इस वजह से उस सीवरेज की पाइपों में इतना पानी कंज्यूम करने की पावर नहीं थी। दूसरे नहरों की सफाई नहीं हुई। मुख्य मन्त्री जी ने इस काम के लिये बर्ड बैंक से लोन ले रखा था लेकिन उनकी सफाई नहीं करवाई। अगर उनकी सफाई हुई होती तो वह पानी उन नहरों में डाला जा सकता था। तीसरी बात यह है कि जो भिवानी में लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम बनी थी। उस पर 68 पम्प थे। वे सारे बन्द पड़े थे। एक तरफ के पम्प बिजली से चलने वाले थे और दूसरी तरफ जनरेटर से चलने वाले थे। उनका भी समय पर अप्रेशन नहीं किया गया। अगर वे पम्प सैट ठीक होते तो यह आफत कम हो सकती थी। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार इन बातों में फेल रही इसलिये हमारे को बड़े दिन देखना पड़ा।

जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, इसके बाँटने में भी धांधली हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसका कोई हिसाब नहीं है। पहले



भी बाढ़ के समय में धांधली हुई थी। जैसा कि मुझे पता है, तीन चार कारणों से ये बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को मैं प्रैक्टिकल फिजर्ज बताना चाहता हूँ। कुछ अधिकारी और नेतागण मिले हुए थे और एक कमरे के लिये दो-दो, तीन-तीन दफा मुआवजा दे दिया। लेकिन जिन गरीब भाइयों के सही भायने में घर गिरे थे उनको मुआवजा नहीं मिला। एक गांव में एक आदमी ने सात हजार रुपये में एक मकान ले लिया और यह कह दिया कि इसका मसवा आप उठा लेना। वह मकान तोड़ रहा था और इतने में बारिश ही गई। उसने दस हजार रुपये उस मकान का भी मुआवजा ले लिया। कईयों ने डबल या ट्रिपल मुआवजा ले लिया। लेकिन जो जहरतमन्द थे उन भाइयों को कुछ नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में मरने वालों के लिये सरकार ने कम्पनसेशन देने का वायदा किया था। मेरे शहर में एक गरीब मनियारी थी जिसका एक ही लड़का था। गांव में छः छः फुट पानी भर गया। उस मनियारी का लड़का डूब कर मर गया। लेकिन उस बेचारी को कोई मुआवजा नहीं मिला क्योंकि वह बेचारी गरीब थी। हनुमानगढ़ी का एक 23 साल का लड़का पानी में डूब कर मर गया लेकिन उसका डैप सर्टिफिकेट अधिकारियों ने नहीं दिया जिसके कारण उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, जो मुआवजा बांटा गया है उसमें बहुत ही धांधली हुई है। मुआवजों के लिए जब पीड़ित लोग हमारे पास आते थे और हम उनको लेकर डी० सी० के पास जाते थे तो डिप्टी कमिश्नर का जवाब होता था कि ये नेता लोग लोगों को लेकर आ जाते हैं, इनकी तो यह आदत है। अध्यक्ष महोदय, जो सुखी होना वह आयेगा ही। अधिकारियों से कहेंगे ही लेकिन पता नहीं कि सरकार के आदेश थे या क्या कारण था कि शहर के अन्दर मुआवजा बंटने में बहुत ज्यादा दिक्कत रही है। जहाँ तक वाटर सप्लाय का सवाल है, मेरे इलाके में खासतौर पर भिवानी जिले की और मैं कई बार सरकार का ध्यान आकषित करा चुका हूँ। आपके माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि प्रायः भिवानी के अन्दर पीने के पानी में सीवरेज का मिक्सड पानी आता है। बाढ़ के बाद तो वाटर सप्लाय रैस्टोर ही नहीं की गई जिससे कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग नहरों और तालाबों का पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। जहाँ तक भिवानी शहर का तालुक है, वहाँ सीवरेज का मिक्सड पानी आता है और वह भी दो टाइम की बजाए एक ही टाइम आता है। वह भी ठीक टाइम पर नहीं आता। इसके साथ-साथ जहाँ तक पानी के बिलों का सवाल है, आपके माध्यम से मैं पब्लिक हेल्थ वालों से पूछना चाहूंगा कि वाटर के बिलों का जो निर्णय सरकार ने लिया है, वह मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं है। जहाँ दस एम० एम० की टूटी होगी इसके लिए 25 रुपये और आधा इंच की टूटी हो तो उसके लिए 40 रुपये का बिल लिया जाता है। दस एम० एम० और आधा इंच में कोई खास फर्क नहीं है। जिस वक्त कनेक्शन दिए थे उस वक्त एम० एम० का कोई सवाल नहीं था और लोगों के आधा इंच के फेइल लगे हुए थे।

[श्री राम भजन अग्रवाल]

मेरे शहर में जहां आधा इंच के फॉल लगे हुए थे वहां पर अधिकारी 40 रुपये का बिल भेजते हैं। यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इसको ठीक करने के आदेश दिए जायें। दूसरी एक गलती यह हो रही है कि अगर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है तो मैं मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि वे और स्टाफ दें चाहे वह बिल कलर्क हो। छ-छ महीने, आठ-आठ महीने, 12-12 महीनों तक के बिल आते हैं। एक गरीब आदमी एक-दो महीने का बिल तो दे सकता है लेकिन हजार-हजार रुपये या दो-दो हजार रुपये का बिल इकट्ठा होकर आये तो वह बिल्कुल अनुचित है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां तक बिलिंग का ताल्लुक है वह दो महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। न कि छ-छ या आठ-आठ महीने का आये। जब लम्प-सम बिल आता है तो उसको भरने में दिक्कत होती है। जो बिल का सिस्टम मीटर दैन वन-टैप का है उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। पानी एक टूटी में नहीं आता और घर में अगर दो या तीन टूटियां लगी हैं तो 40 रुपये पर टूटी का रेट हो गया ये बातें कुछ व्यावहारिक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सुधार करना चाहिए क्योंकि पानी तो मिलता नहीं है, केवल बिल मिलते हैं इसमें सुधार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीवरेज का सवाल है वह बिल्कुल बन्द पड़ी है। चाहे पोलिथिन बैगल की वजह से हो या सीवरेज की कम कैपेसिटी की वजह से हो। शहर के अन्दर सीवरेज का पानी अन्दर फलो कर रहा है। सड़कों के ऊपर पानी भरा पड़ा है और शहर के अन्दर काफी जगहों पर भेन होल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर में कई छोटे-छोटे ऐसे इलाके हैं जहां पर कि सीवर डालना चाहिए, उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां सीवर पड़ी हुई है और केवल पांच या बस फुट का टुकड़ा भेन सीवर से मिलना है। वह अधिकारी नहीं मिला पा रहे हैं जिस कारण 500-600 फुट डाला हुआ सीवर बेकार पड़ा है। इसलिए सरकार ने जो 500 या 600 फुट तक सीवर डाल दी है, वह पैसे का दुरुपयोग हुआ है। सरकार ने और इसके ओफिसर्स ने इन छोटी-2 बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बड़ी बातों की तरफ ये क्या ध्यान देंगे? आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि सीवर के सिस्टम को ठीक किया जाए। जो छोटे इलाके रह जाते हैं जो नालियां रह जाती हैं उनमें सीवर डाली जाए। उसके लिए बजट दिया जाए। जो सीवर कन्वैशन के बगैर पड़ी हैं उनका कन्वैशन मिश्राया जाए। शहर के अन्दर गंदगी का बहुत बुरा हाल है। कोई सफाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अग्रवाल साहब, आप वाइड-अप करें।

श्री राम भजन अग्रवाल : शहरों के अन्दर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो नालियां निकलती हैं उनमें से गंदगी निकाल कर सड़क पर कूड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं। मेरे शहर भिवानी की म्यूनिसिपल कमिटी कुछ झगड़े में पड़ी हुई है। उसका कौन

प्रधान है वही नहीं है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस म्यूनिसिपल कमेटी को सरकार ने जो पैसा दिया है उसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। डी० सी० और एस० डी० एम० के माध्यम से सरकार वह पैसा खर्च करवाए। भिवानी शहर में जो नालियाँ हैं उनकी रिपेयर कराई जाए और वहाँ पर जो गंदगी के ढेर पड़े हैं उनको उठाने के लिए कोई अल्टिमा से पूल बनाया जाए। भिवानी शहर की सफाई का स्टैंडर्ड बहुत थिर गया है। वहाँ पर गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, उसके बारे में कई सदस्यों ने बताया कि सरकार पूरी बिजली देने के प्रयास कर रही है। बिजली मंत्री महोदय भी प्रयास कर रहे होंगे। कारण चाहे कुछ भी हों, चाहे कोई टेक्नीकल तकलीफ हो, चाहे कोई पावर लोड की तकलीफ हो लेकिन मेरे शहर भिवानी में शाम को बिजली नहीं जाती है। मैं चाहूंगा कि कम से कम शाम के समय मेरे शहर भिवानी में बिजली जरूर दी जानी चाहिए क्योंकि शाम को बच्चों की स्टडी का टाइम होता है। द्यूबबैल चलाने का टाइम होता है। जहाँ तक बिजली के बिलों का सवाल है, उसके बारे में मेरा आग्रह है कि बिजली के बिल 5-5 और 6-6 महीने के इकट्ठे आते हैं। मैं चाहूंगा कि दो महीने से ज्यादा के बिल नहीं आने चाहिए क्योंकि लोग इतने लम्बे समय के बिल जमा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए या तो बिजली के बिल मंथली आ जाएं या 2-2 महीने के आ जाएं तो लोगों को बिल की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं होगी।

**श्री अध्यक्ष :** आपके नेता तो कहते हैं कि किसानों से 6 महीने के बाद बिजली का बिल ले लें।

**श्री राम भजन अग्रवाल :** वे ठीक कहते हैं क्योंकि किसानों की दो फसलें होती हैं और उनको द्यूबबैल का बिजली का बिल साल में दो बर्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लिए हमारे नेता की यह जैनुअन बात है। मैं तो डोमैस्टिक बिजली के बिलों के बारे में कह रहा हूँ।

**श्री श्रीरंज सिंह :** स्पीकर साहब, कल चौ० बंसी लाल ने यह कहा था कि बिजली चाहे आप बेशक प्राईवेट सेक्टर से लाओ और चाहे आप इसका प्राईवेटाइजेशन करो लेकिन इसी बात पर कर्ण सिंह दलाल और इनके दूसरे साथी आज सदन से वाक-आउट कर गए थे। यह तो इनकी हालत है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है क्योंकि मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर कहा है कि आज हमने वाक आउट किया था। इन्होंने जो सुझाव दिया था कि ये बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं, हमने उसके प्रोटैस्ट में वाक आउट किया था। चौधरी बंसी लाल जी ने कल यह बात कही थी कि आप किसी प्राईवेट कम्पनी से थर्मल प्लांट बनवा रहे हैं। उसमें हमें कोई एतराज नहीं। चौधरी बंसी लाल जी ने यह बात नहीं कही थी कि बिजली का निजीकरण कर दिया जाए।

श्री राम सजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि जो जन साधारण हैं, जो मूलाग्रिम हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनके बिजली के बिल मंथली या 2-2 महीने के अने चाहिए ताकि उनको बिल की अदायगी में कोई दिक्कत न हो। जहाँ तक द्यूबवैलज की बिजली के बिलों का ताल्लुक है वह साल में दो दफा ही आएँ, क्योंकि किसान तो बिजली का बिल फसल पर ही भर पाएँगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्कूलों के अपग्रेडेशन का सवाल है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के में एक इतलाना गाँव है। वह गाँव जब से बसा है तब से उसमें मिडल स्कूल है, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही एक नांगल गाँव है उसके स्कूल को भी अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। लड़कियाँ तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गाँव के स्कूल में जाने में दिक्कत महसूस करती हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार कम से कम लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करे ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। स्कूलों के अन्दर टीचर्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट के नम्बर आफ स्कूलज की तो कोई लिमिट नहीं है लेकिन स्टाफ वहाँ पर नहीं है जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही। आज एक-एक सेशन में 100-100 से लेकर 150-150 तक बच्चे पढ़ते हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ का पूरा इंतजाम किया जाये। दूसरा मेरा सुझाव है कि स्कूलों में बच्चों के पोषाहार पर जो 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, यह स्कीम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लागू की गई है, ठीक तरह से नहीं चल पा रही। बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ न जा कर इस तरफ ही लगा रहता है कि कब हमें खाने को पूरी मिलेगी जबकि उसकी मात्रा बहुत ही कम है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि या तो इस स्कीम को और पैसा देकर अच्छी तरह से चलाया जाये या इस पैसे से पुस्तकें और वर्दी आदि देकर गरीब बच्चों की मदद की जाए। इस स्कीम से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने के सिवाय अब तक और कुछ नहीं हो रहा। कृपया इस बारे में सरकार गंभीरता से सोचे। इस स्कीम में एक बच्चे को 10 ग्राम के हिसाब से खाने की चीज मुहैया करवाई जा रही है, जिससे कुछ बनने वाला नहीं है। इससे बच्चों का पेट भी नहीं भरता। इसलिए इस स्कीम में सुधार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग का भी स्कूलों की तरह हाल है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज तो खोल दिए गए हैं लेकिन उनमें न तो डॉक्टर हैं और न दवाईयाँ हैं। मंत्री महोदय ने बताया था कि 7-8 रुपया प्रति पेशीट खर्च किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह 7-8 रुपया प्रति पेशीट कैसे खर्च हो रहा है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर केवल एक पची डॉक्टर की तरफ से मिलती है और दवाई

सारी बाहर से लानी पड़ती है। वह दवाई भी वहीँ की लिखता है जहाँ से उसे कमीशन मिलना होता है। इसी प्रकार से ला एण्ड आर्डर की हालत भी बहुत खराब है। मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश में इन तीनों चीजों का, यानि एजुकेशन, स्वास्थ्य और ला एण्ड आर्डर का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये तीनों चीजें ठीक नहीं होंगी, वह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन तीनों मुद्दों की तरफ ध्यान दे और इनमें सुधार करे।

### वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : जॉन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से यह कहा गया कि मैंने बिजली प्राइवेट क्षेत्र में देने को कहा। मैंने यह कहा था कि हमारे जितने भी एटोमिक प्लांट्स हैं, चाहे वे थर्मल प्लांट्स हैं, गैस बेस्ड प्लांट्स हैं या हाईड्रल प्रोजेक्ट प्लांट्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाये लेकिन मैंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि इनका कंट्रोल और बिजली का वितरण बिजली बोर्ड के पास रहे।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

\*17.18 hours | (The Sabha then \*adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 29th February, 1996).

1. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

2. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

3. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

4. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

5. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.



1. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

2. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

3. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

4. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

5. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

1. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

2. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

3. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

4. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.

5. The Hon. Member, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, Punjab, India.